RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ.. सच

Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-02, अंक - 22 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 05 मार्च 2020 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

क्रोध और गुस्सा इंसान को तभी आता है जब वह अपने आपको कमजोर और हारा हुआ मान लेता है।

बीके शिवानी

राष्ट्रपति ने पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज की

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया बलात्कार और हत्याकांड मामले के चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता की दया याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है। अन्य तीनों आरोपियों की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा पहले ही खारिज की जा चुकी है। इससे इन चारों को फांसी दिये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

चारों दोषियों को मंगलवार सुबह फांसी दी जानी थी, लेकिन पवन गुप्ता ने सोमवार को राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका दायर कर दी जिससे उनकी फांसी पर रोक लग गई थी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने उसकी सुधार याचिका को खारिज कर दिया था।

भड़काऊ भाषण: एफआईआर दर्ज करने संबंधी याचिकाएं हाईकोर्ट भेजी

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हिंसा में भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफप्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिकाओं को उच्च न्यायालय को बुधवार को भेज दिया और उसे शुक्रवार को सुनवाई करने का निर्देश दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफप्राथमिकी दर्ज करने के मामले को 13 अप्रैल के लिए टाल दिया था, लेकिन शीर्ष अदालत के आज के निर्देश के बाद अब शुक्रवार को होगी सुनवाई।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने दंगा पीड़ित याचिकाकर्ताओं के वकील कॉलिन गोंजाल्विस को कहा कि वह कुछ राजनैतिक नेताओं के नाम दिल्ली उच्च न्यायालय को सुझाये ताकि वह (उच्च न्यायालय) शांति बहाली की संभावना तलाशने पर विचार करे।

इस बीच शीर्ष अदालत के खिलाफ टिप्पणी की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की शिकायत को लेकर एक याचिकाकर्ता हर्ष मंदर से शुक्रवार तक जवाब देने को कहा।

सोना 1,400 रुपए उछलकर 45 हजार के करीब

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत ब्याज दरों में 0.5 प्रतिशत की कटौती के बाद विदेशों में रही जबरदस्त तेजी से दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना आज 1,400 रुपये की छलाँग लगाकर 44,870 रुपये प्रति दस ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।

सोने में लगातार तीसरे दिन तेजी रही। चाँदी भी 1,250 रुपये उछलकर करीब एक सप्ताह के उच्चतम स्तर 47,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गयी।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद विदेशी बाजारों में मंगलवार को सोना हाजिर तीन प्रतिशत मजबूत हुआ जो 2016 के बाद की सबसे बड़ी एक दिनी तेजी है। इसका असर बुधवार स्थानीय बाजार खुलने पर दिखा।

अधिकारी अपने ही आदेश का पालन नहीं कर रहे, सीएम हेल्प लाईन में शिकायत दर्ज

राजस्व न्यायालय के चक्कर लगा रहा बुजुर्ग, अधिकारियों के दुर्व्यवहार की भी बात आ रही सामने

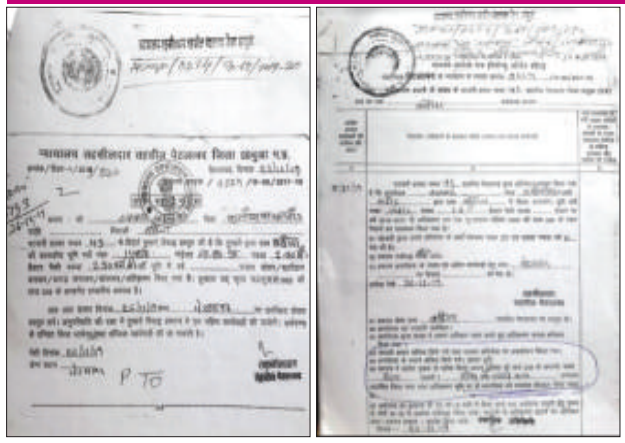

अतिक्रमण कर्ता को तहसील न्यायालय से जारी नोटिस और अतिक्रमण से बेदखली के आदेश की प्रति।

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

भू-माफिया को हटाने का दावा करती प्रदेश की कांग्रेस सरकार की मंशा पर उसका प्रशासन पानी फैरता नजर आ रहा है। एक दो नहीं कई मामलों में पेटलावद का राजस्व अमला बड़े भू-माफियाओं और अतिक्रमणकर्ताओं से सांठ-गांठ कर उनको बचाता नजर है। पेटलावद राजस्व न्यायालय में कई मामले या तो लटके पड़े है या फिर उनमें दिए गए आदेशों का पालन नही हो पा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पेटलावद निवासी रामलाल पिता गणपत सोलंकी जो कि 70 वर्षीय बुजुर्ग है। जो अतिक्रमणकर्ता के कब्जे से न केवल खुद की बल्कि शासकीय भूमि छुटवाने के लिए संघर्ष कर रहा हैं। मामले में तहसील न्यायालय पेटलावद द्वारा अतिक्रमणकर्ता राजमल राठौर को हटाने के आदेश और अर्थदंड के आदेश तक कर दिए, लेकिन दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अतिक्रमणकर्ता को नहीं हटाया जा सका है।

ये है मामला

रामलाल सोंलकी निवासी पेटलावद ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में बताया गया कि ग्राम पंचायत खोरिया के ग्राम बरडिया प.ह.न. 45 में स्थित शासकिय भूमि सर्वे नंबर 148/2 मद नाकाबा रकबा 1.00 हैक्टर की भूमि पर लगभग 2500स्कवेयर फीट भूमि पर अर्द्ध पक्का मकान अवैध रूप से राजमल राठौर निवासी पेटलावद द्वारा किया। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान नगर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। राजमल का अतिक्रमण नहीं हटाया गया। एक ओर तो पूरा राजस्व विभाग पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने में लगा था। वहीं उक्त मामले में तहसील में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। उक्त शिकायत के बाद पटवारी द्वारा मौका पंचनामा बनाया गया। जिसमें मौके पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होना पाया गया। राजस्व रिकॉर्ड की जांच करने के बाद मामले में अतिक्रमणकर्ता का अवैध कब्जा शासकीय भूमि पर पाया गया। जिसके बाद पूर्व तहसीलदार मुकेश कासिव द्वारा उक्त प्रकरण क्रमांक/0224/अ-68/2019-20 में दिनांक 26.12.2019 को आदेश जारी किया गया। जिसमें अतिक्रमणकर्ता का अवैध कब्जा भूमि से हटाकर बेदखली और पांच सौ रूपये जुर्माना वसूले जाने के आदेश जारी किए। लेकिन राजस्व का अमला अपने ही आदेश के पालन के लिए न तो खुद कोई प्रयास किए न ही हल्के के पटवारी को उक्त मामले में आज तक कोई सूचना देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए। मामले में ग्राम बरडिया के पटवारी से जब चर्चा की गई उन्होने बताया कि मेरे द्वारा अधिकारी के आदेशानुसार मौका पंचानामा बनाकर पेश कर दिया गया था। इसके बाद की कार्यवाही अधिकारियों को ही करनी है। मेरे पास अभी तक कोई नोटिस या जानकारी अधिकारी की ओर से नही आई है। दो माह पूर्व हुए आदेश के पालन के लिए तहसील न्यायालय से कोई प्रयास किया गया। इससे साफहोता है जवाबदार अधिकारी अतिक्रमणकर्ता से सांठ-गाठ कर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास कर रहे है।

फुटबाल बना बुजुर्ग शिकायतकर्ता

पेटलावद तहसील न्यायालय से न्याय नहीं मिलने से परेशान बुजुंग रामलाल सोंलकी द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष दिनांक 21.01.2020 को जन सुनवाई में आवेदन लगाकर राजस्व विभाग से तहसील कार्यलय द्वारा जारी आदेश के पालन कराए जाने की गुहार लगाई। पूरा प्रकरण सुनने समझने के बाद जिला कलेक्टर द्वारा मामले पर कार्यवाही करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के पास भेज दिया। जनसुनवाई के शिकायत में मिले आश्वासन के आधार पर शिकायतकर्ता अनुविभागीय अधिकारी एमएल मालवीय के समक्ष पहुंचा तो एसडीएम बुजुर्ग की समस्या सुननें और अपने जिला अधिकारी के आदेश के पालन करने की बजाए शिकायतकर्ता को ये बोलकर रवाना कर दिया ये मेरा मामला नहीं है। तहसीलदार के पास जाओं। तब से लेकर अब तक बुजुंग रामलाल झाबुआ, पेटलावद हर मंगलवार चक्कर लगा रहा है। जिला कलेक्टर हर बार तहसीलदार और एसडीएम से मिलने का बोलकर रवाना कर देते हैं। वहीं राजस्व के अधिकारियों न तो स्वयं के न्यायालय के आदेश की परवाह है, न ही बुर्जुग की उम्र की। ऊपर से उसके साथ दुर्व्यवहार पर उतारू होकर उसी को खरी खोटी सुना भगा दिया जाता हैं।

सीएम हेल्प लाइन पर लगाई गुहार

अधिकारियों के गलत बर्ताव और आदेश के पालन नहीं होने से परेशान बुजुर्ग ने सीएम हेल्प लाइन पर गुहार लगाकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। जिसमें अधिकारियों द्वारा मामले में कार्यवाही नहीं करने और दुर्व्यव्हार की शिकायत की गई। सीएम हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक 10415947 से मिले आश्वासन के बाद रामलाल को कार्यवाही की उम्मीद है। पूरे मामले में अतिक्रमणकर्ता ने न्यायालय के समक्ष झूठी और भ्रामक जानकारी देकर न्यायालय को गुमराह करने का भी प्रयास किया। अतिक्रमणकर्ता राजमल द्वारा एक नहीं अन्य स्थानों पर भी शासकीय भूमि पर कब्जा कर भवन निर्माण कर लिया गया। जिसका खुलासा भी माही की गूंज में किया जाएगा।

16 साल की शेफाली टी-20 रैंकिंग में बनीं नंबर एक

दुबई,एजेंसी। आईसीसी टी-20 महिला विश्वकप में विस्फोटक प्रदर्शन कर रहीं भारत की 16 साल की युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा आईसीसी की ताजा टी-20 रैंकिंग में बुधवार को शीर्ष स्थान पर पहुंच गई।

शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया में चल रहे में विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया है जिसका फायदा उन्हें बल्लेबाजों की रैंकिंग में मिला। शेफाली ने 19 स्थानों की लम्बी छलांग लगाकर 761 रेटिंग अंकों के साथ इस सूची में पहले स्थान हासिल कर लिया जबकि न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 750 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

राज्यसभा के लिए जारी है हॉर्स ट्रेडिंग

माही की गूंज, भोपाल।

सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा की ओर से कांग्रेस विधायकों को 25 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है और उनको तोड़ने का प्रयास हो रहा है। यह मामूली आरोप नहीं है। असल में इस महीने के अंत में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह के प्रयास हो रहे हों तो हैरानी की बात नहीं होगी। 26 मार्च को राज्य की तीन लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। कमलनाथ सरकार का भविष्य इस चुनाव से जुड़ गया है। अगर कांग्रेस अपनी संख्या के दम पर दो सीटें जीत लेती है तो इससे सरकार को नया जीवनदान मिलेगा। लेकिन अगर भाजपा दो सीटें जीतती है तो सरकार का गिरना तय हो जाएगा।

फिलहाल सरकार का पलड़ा भारी दिख रहा है क्योंकि सरकार के पास राज्य की 230 सदस्यों की विधानसभा में 121 का समर्थन है। इसमें कांग्रेस के अपने 114 विधायक हैं। इनके अलावा बसपा के दो, सपा के एक और चार निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी सरकार को है। दूसरी ओर भाजपा के पास 107 विधायक हैं, जिनमें से दो विधायकों- नारायण त्रिपाठी और शरद कोल का समर्थन कांग्रेस को मिल सकता है। दो सीटें खाली हैं। मौजूदा 228 की संख्या के हिसाब से राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोट की जरूरत है। कांग्रेस के पास चूंकि 121 का समर्थन है इसलिए उसे आसानी से दो सीटें मिलनी चाहिए। अगर भाजपा दूसरी सीट जीतना चाहती है तो उसे कम से कम नौ सीटों का इंतजाम करना होगा, जो मौजूदा हालात में मुश्किल लग रहा है। ध्यान रहे मध्य प्रदेश से कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा के प्रभात झा व सत्यनारायण जटिया रिटायर हो रहे हैं।

न्यायालय के निर्णय के बाद भी नहीं खुल रही स्वास्थ्य विभाग की नींद

मामला : बरवेट में दो वर्ष से लटके उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का

माही की गूंज, पेटलावद।

पिछले दो वर्ष से भी अधिक समय से ग्राम बरवेट का उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत से अटका पडा है। मामले में व्यवहार न्यायाधीश सूर्यपालसिंह राठौर द्वारा भूमि पर अपना स्वामित्व बता रहे सभी 06 लोगों के स्टे आवेदनों को खारिज किया गया है। दावा अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। वादी पक्ष की साक्ष्य हेतु अगली पेशी निर्धारित है। जिसमें दोनों पक्षों को न्यायालय में साक्ष्य पेश करवना है। साक्ष्य के बाद ही न्यायलय से गुण दोष पर निराकरण संभव हैं। उक्त भूमि पर शासन चाहे तो उपस्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवन का निमार्ण कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का अमला और कार्य के ठेकेदार मामले में भवन बनाने में कोई रूचि नहीं दिखाई जबकि न्यायालय से पहले ही उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिये आंवटित भूमि पर निर्माण करने के लिए रोक लगाये जाने की अपील खारिज हो गई थी। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत बरवेट द्वारा राजस्व विभाग को आवेदन देकर भूमि खाली करवा कर निर्माण कार्य शुरू करवाने के मांग की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा विवादित भूमि पर कब्जाधारियों ने रात-दिन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी सांरगी नायाब तहसीलदार को लगने पर दिन-रात दस कोटवार की ड्युटी लगा दी थी। पूरे मामले को माही की गूंज द्वारा सिलसिले वार उठाया गया। जिसके बाद प्रशासन हरकत में भी आया। स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ कार्य के ठेकेदार को भी मौके पर ले जाकर भूमि नाम कर कार्य शुरू करने का कहा गया। लेकिन ठेकेदार ने निर्माण में कोई रूचि नहीं दिखाते हुए मामला न्यायालय में होने और निर्माण के दौरान विवाद की स्थिति को बोलकर निर्माण कार्य टलता रहा। वहीं विभाग के जवाबदार अधिकारी भी पूरे मामले में निर्माण को लेकर गंभीर रूचि नहीं दिखा रहे हैं।

दबंग अतिक्रमणकर्ताओं ने कर दिया निर्माण कार्य शुरू

कलेक्टर ने आंवटित की थी भूमि

ग्राम बरवेट में मॉर्निंग फॉलोअप पर पहुंचे पूर्व कलेक्टर आशीष सक्सेना को ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए भूमि की मांग थी। जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व की टीम ने बरवेट हल्के में सर्वे नंबर 409 पर भवन बनना प्रस्तावित कर पूरा प्रकरण बनाकर कलेक्टर की सहमति लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्माण हेतु भूमि आवंटित कर दी थी। लेकिन निर्माण स्थल पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा था। जिसको हटाने के लिए राजस्व अमला मौके पर पहुंचा था। जहां राजस्व की टीम पर कब्जाधारियों और उनके सहयोगियों ने हमलाकर दिया था। पूर्व नायाब तहसीलदार सोंलकी के साथ हाथपाई की गई थी। मामले में 09 लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा 353, 151 के तहत रायपुरिया थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले को बाद में कब्जाधारियों द्वारा न्यायालय में ले जाया गया। जहां से कब्जाधारियों को किसी प्रकार का स्टे नहीं मिला। लेकिन न्यायालय ने प्रकरण स्वीकार लिया। जिसकी आड में अब तक कब्जाधारी मामले के न्यायालय में होने की आड़ में अब तक स्वास्थ्य विभाग को कार्य करने में रोकने में सफल हो रहे थे। इस बीच कब्जाधारियों द्वारा अवैध निर्माण करने का भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके।

ग्राम पंचायत ने की मांग

न्यायालय के निर्णय के बाद ग्राम पंचायत सचिव कैलाश भाभर द्वारा फैसले की प्रमाणित प्रति अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार पेटलावद को देकर भूमि पर से कब्जा हटाने और स्वास्थ्य विभाग से निमार्ण कार्य शुरू करवाने का निवेदन किया। ग्राम पंचायत सचिव कैलाश भाभर ने बताया कि एसडीएम एमएल मालवीय द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित कर जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने की बात कही है। जवाबदारों के अब तक के ढूलमूल रवैये के चलते उक्त भवन दो वर्ष के अधिक समय से लटाक पड़ा है। पूरे मामले में राजनैतिक दबाव साफदेखा गया। कई बार अधिकारियों पर दूसरी भूमि आवंटित करने के लिए भी दबाव बनाया गया। अब न्यायालय के निर्णय के बाद ग्राम बरवेट के ग्रामीणों को एक आश बंधी है कि जल्द ही जर्जर भवन से छुटकारा मिलकर कर नया भवन व अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी।

पप्पू टोपी को कांग्रेस में लो, एक हजार रूपए मेरी ओर से

शासकीय शिक्षक एवं सरपंच पति निपटा रहा भाजपा को

माही की गूंज, बामनिया।

कहते है सत्ता के आगे शानपत नहीं चलती और कांग्रेस सरकार में तो बिलकुल नहीं। भाजपा सरकार के समय खुल कर भाजपा की राजनीति करने वाले बामनिया संरपच पति और शासकीय शिक्षक संजय मखोड सरकार बदलते ही कांग्रेस नेताओं की गोदी में बैठ गया। ग्राम पंचायत चुनाव में उक्त कर्मचारी की पत्नी भाजपा के समर्थन से रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने में लगी हैं, तो उसके पति द्वारा अब कांग्रेस के इशारे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का तोड़ने के लिए ईनाम की व्यवस्था की जा रही है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस को धूल चटाने के बाद सत्ता परिवर्तन होते ही शिक्षक का ट्रांसफर भी तय हो चुका था। स्थानीय कांग्रेस नेताओं की ओर से शिक्षक का नाम भी पहले स्थान पर था, लेकिन शिक्षक ने सत्ता परिवर्तन के बाद प्रभावी हुए नेताओं से ऐसी जोड जुगाड बैठाई की न केवल अपना स्थानान्तरण रूकवा लिया, बल्कि कांग्रेसी नेताओं के इशारों पर भाजपा कार्यकर्ताओं को तोड़ने पर ईनाम भी रखने लग गया। गत दिनों अतिक्रमण के शिकार कुछ भाजपाइयों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, तो शिक्षक महोयद को पता नहीं क्या सूझा अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव में समर्थन देने वाली पार्टी के नेताओं को तोड़ने के लिए ईनाम तक की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को कर दी। सरपंच पति द्वारा काजलिया के कांग्रेसी कार्यकर्ता के वाट्स एप्प पर मैजेस भेज कर भाजपा से कांग्रेस में गए सदस्यो के लिए बधाई देते हुए कहा गया कि यदि टोपी को भी कांग्रेस में ले जाते हो, तो मेरी ओर से एक हजार रूपए का ईनाम दूंगा। इतना ही नहीं जिन सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। उनको पहले से कांग्रेसी बताया। चलो अब पप्पू टोपी के बारे मे भी जान लिया जाए। ये टोपी और कोई नहीं पूर्व भाजपा समर्थित पंच है, जो पूर्व सरपंच के निधन के बाद भाजपा के समर्थन से तीन माह तक प्रभारी सरपंच रहा। वर्तमान में उक्त भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी ग्राम पंचायत में पंच है। शिक्षक महोदय अपना मूल कार्य छोड़कर राजनीति करने में ही लगे रहते है। अपनी स्कूल से ज्यादा पंचायत के कार्यों पर ज्यादा ध्यान रखते है। जिसके लिए गांव में सूचना के आदान-प्रदान का एक वाट्स एप्प ग्रुप भी बनाया है। जिसके शिक्षक महोदय स्वयं एडमिन है और ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत के द्वारा किये जा रहे कार्यो की जानकारी देते है। ग्रुप की सेटिंग ऐसी की केवल एडमिन मैसेज कर सकता है। गांव की समस्या को अगर उठाना है, तो ग्रुप में मैसेज करने का प्रावधान नहीं है। भाजपा सरकार के शासनकाल में राजनीति चमकाने वाले कई कर्मचारी कांग्रेस सरकार के निशाने पर थे, लेकिन समय बदलते कांग्रेस ने भी अपनी पॉलिसी परिवर्तित कर दी और अब सुविधा और सुरक्षा की डील पर ऐसे कर्मचारियों को राजनैतिक सरक्षण देकर अपने हित के लिए उपयोग कर रहे है। वहीं चुनाव के दौरान भाजपा के समर्थन से अपनी पत्नी को विजय बनवाने वाले शिक्षक महोदय अब भाजपा की ही जड़े खोदने मे लगें है। यहां मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।

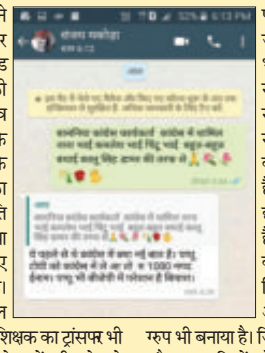

मध्यप्रदेश में नए बजट को तैयार करने की कवायद तेज

बजट में इस बार राज्य सरकार का नए तरीके से राजस्व बढ़ाने पर रहेगा पूरा जोर

भोपाल

कमलनाथ सरकार द्वारा नए बजट को तैयार करने की कवायद तेज कर दी गई है। सरकार द्वारा बजट में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। आ रही खबरों के मुताबिक सरकार नए बजट में आय वृद्धि के साथ ही आम जनता को राहत देने वाले बजट की पूरी तैयारी कर रही है। जिससे माना जा रहा है कि इस बार का बजट लोक-लुभावन वाला होगा। दरअसल नए वित्त वर्ष में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होना है। सरकार हर हाल में इन दोनों ही चुनावों में पार्टी की जीत चाहती है। यही वजह है कि इस बार सरकार जनता के ऊपर कर का कोई नया बोझ डालने के पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही बजट में सरकार को पूरा फोकस आय वृद्धि पर रहने वाला है, इसकी वजह है इस साल प्रदेश के खजाने को को केंद्र से मिलने वाले करों में की गई 14 हजार 233 करोड़ रुपए की कटौती।

आय वृद्धि के लिए सरकार इस बार कर संग्रहण व्यवस्था में कसावट के साथ खनिज, आबकारी और परिवहन से होने वाली आय में वृद्धि पर पूरा ध्यान केन्द्रित करने जा रही है। उधर, हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए एयर टरबाइन फ्यूल (एटीआर) पर लगने वाला वेल्यू एडेड टैक्स (वैट) 24 से घटाकर चार प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

वचन पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी

सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने प्रारंभिक तौर पर बजट का जो खाका खींचा है, उसमें नया कर लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्तमंत्री भी इसके संकेत दे चुके हैं कि आर्थिक मंदी और केंद्र सरकार के असहयोग के बाद जनता पर नए कर का बोझ नहीं डाला जाएगा। वचन पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी, जिसकी पूर्ति ऐसे माध्यमों से की जाएगी, जो सीधे जनता को प्रभावित नहीं करेंगे। सरकार नए वित्तीय वर्ष में मौजूदा कर संग्रहण व्यवस्था में कसावट लाने की रणनीति पर शुरुआत से काम करेगी।

सवा दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट

प्रदेश के बजट का आकार सवा दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहेगा। पहले वित्त विभाग ने केंद्रीय करों में कटौती और आगामी वित्तीय वर्ष में भी केंद्र सरकार से अधिक सहायता की उम्मीद न होने की वजह से बजट का आकार दो लाख करोड़ रुपए के आसपास रखने पर विचार किया था। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ अब बजट वर्क का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने साफ कर दिया कि बजट के आकार में कमी नहीं होगी। वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से आय बढ़ाई जाएगी।

एयर टरबाइन फ्यूल पर घटेगा वैट

बताया जा रहा है कि खनिज, परिवहन, आबकारी, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क से होने वाली आय के लक्ष्य में वृद्धि की तैयारी है। वाणिज्यिक कर विभाग एयर टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले वैट को घटाने का प्रस्ताव दे चुका है। दरअसल, विभाग का मानना है कि टैक्स कम रहने से वायुसेवा सुविधा बढ़ेगी और इससे दूसरी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जो राजस्व दिलवाएंगी। भोपाल में 24 प्रतिशत एयर टरबाइन फ्यूल लिया जाता है, जो इंदौर और ग्वालियर में पहले ही घटाकर चार प्रतिशत किया जा चुका है। एक छतरी के नीचे लाई सकती हैं बच्चों और महिलाओं से जुड़ी योजनाएं सरकार बच्चों और महिलाओं को लेकर स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास से लेकर अन्य विभाग योजनाएं संचालित करते हैं। इन योजनाओं पर विचार करने के लिए गठित अधिकारियों के समूहों ने वित्त विभाग को यह सुझाव दिया है कि समान प्रकृति की योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाया जाना चाहिए, इससे हितग्राहियों को बेहतर तरीके से लाभांवित किया जा सकता है।

वित्त विभाग ने महिला बाल विकास से मांगी जानकारी

बड़े वर्ग को साधने के लिए कमलनाथ सरकार एक नया प्रयोग करने जा रही है। चाइल्ड बजट प्लानिंग के जरिए कमलनाथ सरकार देश में फिर एक नया और अनोखा मास्टर प्लान लाने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने प्लान का मसौदा तैयार किया है और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए विभाग के अधिकारी अन्य राज्यों के आंकड़े जुटाने पर फोकस कर रहे हैं। दरअसल साल 2020-21 के बजट में इस बार बच्चों के लिए अलग से चाइल्ड बजट प्रस्तुत किए जाने की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग के अधिकारी इस बार दूसरे राज्यों के बजट का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। अफसर ऐसी योजनाओं की तलाश कर रहे हैं जो छात्रों, युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। इसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके खेल कूद समेत बहुत सी बातों का समावेश किया जा सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस पर बच्चों को लेकर संवेदनशील है और यही कारण है कि उसके लिए बजट में विशेष प्रावधान करने जा रही है। चाइल्ड बजट को लेकर वित्त विभाग ने इसको लेकर स्कूल, उच्च और महिला बाल विकास विभाग से जानकारी मांगी है।

बजट सत्र में सरकार को घेरने बनाई रणनीति

संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं होने पर सड़कों पर उतरेगी भाजपा

भोपाल

मध्य प्रदेश के आगामी बजट सत्र के दौरान कमलनाथ सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है इसकी शुरूआत भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों के साथ हुई। इसके बाद इंदौर एवं उज्जैन संभाग के विधायकों की बैठक हो रही है।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, "मध्यप्रदेश में शासन एवं प्रशासन संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता पूरे मध्यप्रदेश में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।"

एकजुटता का दिया संदेश

सूत्र बताते हैं कि भाजपा इस बात को लेकर पुख्ता होना चाहती है कि यदि फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती है तो पिछली बार की तरह विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कौल जैसे नए नाम सामने न आएं। कई विधायकों की ओर से पिछले दिनों संगठन के कामकाज पर भी सवाल उठाए गए थे। संभागवार विधायकों की बैठक में तमाम पदाधिकारियों ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। इस एक जुटता को विधानसभा उपचुनावों, राज्यसभा चुनाव, बजट सत्र में दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सत्र में विधायकों की समस्या और क्षेत्रीय समस्याओं पर भी चर्चा की गई।

सांसद की गिरफ्तारी नहीं सहेगी भाजपा

आगर में देवास सांसद महेंद्र सोलंकी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने यह बता दिया है कि अब वह पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर आई है, सांसद की गिरफ्तारी भाजपा नहीं सहेगी वह सड़क पर उतरेगी।

जौरा-आगर उपचुनाव की भी तैयारी बैठक में जौरा और आगर के उपचुनाव पर भी बात हुई। भाजपा के प्रदेश के नेताओं ने तय किया कि इन सीटों के कार्यक्रम भी समानांतर चलें। लिहाजा, आगामी 4 मार्च को आगर-मालवा में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। इसके बाद मुरैना की जौरा सीट का भी कार्यक्रम होगा। राज्यसभा सीटों के नामों को लेकर चर्चा कुछ दिन बाद शुरू होगी। साथ ही, सत्र में विधायकों की समस्या और क्षेत्रीय समस्याओं पर भी चर्चा की गई। विश्वास सारंग ने कहा कि मौजूदा सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है।

मंत्रालय के समक्ष राष्ट्र-गीत व राष्ट्र-गायन सम्पन्न

भोपाल। मुख्य सचिव एसआर मोहन्ती की उपस्थिति में मंत्रालय के समक्ष सरदार पटेल पार्क में पूर्वान्ह 11 बजे राष्ट्र-गीत 'वंदे-मातरम' और राष्ट्र-गान 'जन गण मन' का सामूहिक गायन संपन्न हुआ। इससे पूर्व पुलिस बैंड ने शौर्य स्मारक से सरदार पटेल पार्क तक मार्च करते हुए देश भक्ति के गीतों की धुनें प्रस्तुत की। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मती दीप्ति गौड़ मुखर्जी, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संजय कुमार शुक्ल, सचिव सामान्य प्रशासन आशीष सक्सेना गायन में शामिल हुए। मंत्रालय, सतपुड़ा एवं विध्यांचल भवन स्थित शासकीय कार्यालयों के अधिकारी तथा कर्मचारी इस मौके पर उपस्थित थे।

बोर्ड परीक्षाओं के बाद करें विद्युत मेन्टेनेंस

भोपाल। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही विद्युत मेन्टेनेंस करें। इस दौरान विद्युत प्रदाय सुचारू रखने के लिए आवश्यक कार्य ही करें। विद्युत मेन्टेनेंस अप्रैल माह में करें। ऊर्जा मंत्री सिंह ने कहा कि मेन्टेनेंस शिडयूल को कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी मिल सके। मेन्टेनेंस शेडयूल मॉनीटरिंग के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए।

कांग्रेस में यूथ अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया शुरू

युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए दावेदारों ने दिए साक्षात्कार

भोपाल

युवा कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया में शामिल इंटरव्यू को लेकर बयानबाजी कर रहे नेताओं के तेवर नरम पड़ गए हैं। दरअसल आज सुबह स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अब्राहम राय मणि ने दो टूक कह दिया कि इंटरव्यू पर आधारहीन बयानबाजी करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।

इस बयान के बाद युवा कांग्रेस चुनाव के लिए इंटरव्यू देने को लेकर चल रहा घमासान फिलहाल टल गया है। अब्राहम राय मणि ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंटरव्यू की व्यवस्था राष्ट्रीय नेतृत्व की है इसलिए इस पर गलत बयान देना या विरोध करने वालों पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाएगी। बयान के बाद विरोध के सुर धीमे हो गए। इसके बाद प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल माने जा रहे नेताओं ने हुए इंटरव्यू दिया।

3 मिनट का इंटरव्यू

इंटरव्यू स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अब्राहम राय मणि के अलावा युवा कांग्रेस के भैया पवार 3 से 4 मिनट के अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं। जिसमें दावेदार से उनके परिवार के बारे में पूछा जा रहा है। उनके पिछले साल के पार्टी को लेकर काम-काम से जुड़ा सवाल भी किया जा रहा है।

जारी होगी लिस्ट : प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर मसरूद मिर्जा ने बताया कि इंटरव्यू के बाद जो चुनाव लड़ने की पात्रता रखने वाले होंगे उनकी सूची जारी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि लिस्ट जारी होने के बाद घमासान की स्थिति बन सकती है। दरअसल यदि इसमें कुछ नेता का नाम छोड़ दिया गया तो उसमें घमासान की स्थिति बन सकती है।

इंटरव्यू गलत दिन रखा

- इंटरव्यू गलत दिन रखा, इससे सदस्यता पर असर पड़ेगा। चुनाव में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। राहुल गांधी के इस सिस्टम पर विश्वास है। **पवन जायसवाल, दावेदार**
- मैंने इंटरव्यू दे दिया है। साथ ही यह भी बात रखी कि अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, इसलिए सभी लोग नहीं आ सकते। इसे भी ध्यान में रखा जाए। **विवेक त्रिपाठी, दावेदार**
- मैं इंटरव्यू तो नहीं दूंगा, लेकिन अपना बॉयोडाटा दूंगा। मैंने अभी तक जो भी काम किए हैं वह बॉयोडाटा में लिख कर दे दूंगा। **कृष्णा घाडगे, दावेदार**

नेता विपक्ष गोपाल भार्गव ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप

प्रदेश में किसान परेशान और जनता हलाकान कांग्रेस सरकार ने काम नहीं, बयानबाजी की

भार्गव बोले- सरकार कभी आईफा, तो कभी महिलाओं के लिए शराब आउटलेट खोलती

कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 14 महीने विकास के कोई काम नहीं किए

भोपाल। विधानसभा में नेता विपक्ष गोपाल भार्गव ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। कहा- पिछले 14 माह में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने केवल बयानबाजी की है, प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया। भार्गव ने ट्वीट के जरिए राज्य की कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मूल मुद्दों के बजाय प्रदेश सरकार कभी आईफा, तो कभी महिलाओं के लिए शराब आउटलेट, तो कभी नई शराब नीति से शराब माफिया को संरक्षण की बात करती है।

मायावी वचनों को समझ चुकी जनता

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को जनता की समस्याओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ हर वर्ग में आक्रोश है। किसान परेशान और जनता हलाकान है। मुख्यमंत्री सिर्फ उपचुनाव में जाकर 2 लाख की कर्जमाफी की घोषणा करते हैं, ताकि सरकार के प्रति जनता के आक्रोश को दबाया जा सके, लेकिन जनता कांग्रेस के मायावी वचनों को समझ चुकी है। पिछले वर्ष भी किसानों को अतिवृष्टि की मार झेलनी पड़ी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भेजी एक हजार करोड़ की राशि वितरित नहीं की।

धरना दे रही महिला अतिथि विद्वान ने कराया मुंडन

भोपाल। नियमितिकरण को 84 दिन से धरना-प्रदर्शन कर रहे अतिथि विद्वानों में से एक महिला ने सोमवार को मुंडन कराया। करीब 10 दिन पहले भी एक महिला अतिथि विद्वान ने मुंडन कराया था। अतिथि विद्वानों का कहना है कि 8 मार्च यानि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिला अतिथि विद्वान सामूहिक रूप से मुंडन कराएंगी। धरना भोपाल के शाहजहांनी पार्क में चल रहा है। अतिथि विद्वान संघ के संयोजक डॉ. देवराज सिंह ने बताया कि 84 दिन बीतने के बाद भी मांग अधूरी है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी महिला अतिथि विद्वान मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराएंगी।

1250 पदों पर होगी अतिथि विद्वानों की जल्द भर्ती: इधर, उच्च शिक्षामंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान किया है। मीडिया से पटवारी ने कहा कि अतिथि विद्वानों के 1250 पदों की वैकेंसी जारी हो रही है। उन्होंने कहा कि एक-एक अतिथि विद्वान को काम पर रखा जाएगा। एक भी अतिथि विद्वान बाहर नहीं किया जाएगा। अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण के लिए कर्मचारी आयोग बनाएंगे।

डिंडौरी और छिंदवाड़ा जिले के 171 देव स्थानों का होगा जीर्णोद्धार

आस्थान योजना में डिण्डोरी जिले के 23 ग्रामों में बनेंगे सामुदायिक भवन

भोपाल

राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण की आस्थान योजना में इस वर्ष डिण्डौरी जिले के 23 ग्रामों में 10-10 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही डिण्डौरी जिले के 50 और छिन्दवाड़ा जिले के 121 देव स्थानों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए की लागत से आदिवासियों के देव स्थानों के जीर्णोद्धार के कार्य कराए जाएंगे। कार्यों में चबूतरा निर्माण और फेन्सिंग कार्य प्रमुख हैं। आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई। आस्थान योजना में पहले वर्ष में मण्डला के चौगान स्थल, छिंदवाड़ा के हरियागढ़ और झाबुआ के बारादेव में 50-50 लाख रुपए के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई।

10-10 लाख रु. की लागत से बनेंगे भवन

डिण्डौरी जिले के जिन 23 ग्रामों में 10-10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनेंगे, उनमें ग्राम नारायणडीह, बरैचा, जोगीठिरिया, नेवसा, बीजापुरी, मुकुटपुर, मोहती, समनापुर, अण्डई, पौडी, चांडा, गिरवरपुर, मझिगखार, केवलारी, खुरखुरी दादर, मुसन्डा, झनकी, मूसामुण्डी, प्रिण्डसरयी, मसूरधुवरी, चौगान, चुरिया और कलवाखोरी शामिल हैं।

दीपक बाबरिया सत्ता व संगठन में करेंगे समन्वय

भोपाल। सत्ता और संगठन में समन्वय के लिए दो दिन तब बैठक करने के लिए आ रहे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया इस दौरे में कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे। इस दौरान वे बीआईपी गेस्ट हाउस में मंत्रियों से भी वनटू-वन चर्चा करेंगे।

हालांकि सभी मंत्रियों से चर्चा करने का उनका प्रोग्राम नहीं है। करीब एक दर्जन मंत्रियों से उनकी मुलाकात हो सकती है। विभिन्न संगठनों के साथ बैठक में सत्ता और संगठन में समन्वय को लेकर आ रही परेशानी से मंत्रियों को रूबरू करवाने के बाद उसे हल करने के निर्देश दे सकते हैं।

विभागों के अध्यक्षों से लेंगे रिपोर्ट

दीपक बाबरिया चार मार्च तक भोपाल में रहेंगे। तीन मार्च को सुबह 11 बजे वे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मोर्चा संगठन और विभागों के अध्यक्षों के साथ ही चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बाबरिया ओबीसी, अजा, अजजा, किसान कांग्रेस, संवादल सहित कांग्रेस के अन्य विभागों के प्रमुखों से उनके संगठन के कामकाज की रिपोर्ट लेंगे। इस दौरान सत्ता और संगठन से उनके तालमेल की भी जानकारी ली जाएगी। इस बैठक में चंद्रप्रभाष शेखर, राजीव सिंह सहित पीसीसी के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

वर्ष 2019 में 7 लाख मिट्रिक टन गेंहू केन्द्र ने नहीं लिया, खरीदी से पहले किसान हुए चिंतित

इस वर्ष मध्यप्रदेश में गेहूं के बोनस पर मंडराए संकट के बादल!

भोपाल/जबलपुर

धान को लेकर केंद्र और राज्य की लड़ाई का खामियाजा भुगतने वाले प्रदेश के अन्नदाता को गेहूं बोनस मिलने की उम्मीद कम ही रखनी चाहिए। दरअसल, केंद्र सरकार राज्य से कई लाख मिट्रिक टन गेहूं नहीं खरीद रही है। बोनस को लेकर केंद्र और राज्य की लड़ाई भले ही ठनी हो लेकिन अन्नदाता के पास अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। रबी फसल खेतों में लहलहा रही है और जल्द ही सरकारी खरीदी के लिए खरीदी केन्द्र में लाई जाने वाली है। पिछले साल 2019 का सेंट्रल पूल का करीब 7 लाख मिट्रिक टन से ज्यादा गेहूं केन्द्र सरकार ने नहीं खरीदा था। इस वजह से किसानों को पिछले साल का बोनस भी नहीं मिल सका है। वहीं इस साल खरीदी से पहले किसान चिंता में हैं।

कमलनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद 5 मार्च 2019 को गेहूं उत्पादक किसानों को 160 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की थी। इसमें उपार्जन केंद्रों पर गेहूं बेचने वालों के साथ मंडी में उपज बेचने वाले किसान भी शामिल किए गए हैं। बजट में सरकार ने 1,462 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया। खरीदी का काम जब खत्म हो गया तब केंद्र सरकार ने सेंट्रल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरत से ज्यादा गेहूं लेने से इंकार कर दिया। जबकि, केंद्र सरकार के साथ खरीदी के पहले 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं सेंट्रल पूल में लेने पर सहमति बनी थी। इस बारे में केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया गया कि केंद्र और राज्य के बीच 2016 में अनुबंध हुआ था कि विकेंद्रीकृत उपार्जन व्यवस्था में बोनस नहीं दिया जाएगा। केन्द्र ने माना कि प्रदेश सरकार ने जब किसान समृद्धि योजना में जो प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान रखा है, वो बोनस ही है और इस तरह के कदम से बाजार प्रभावित होता है।

प्रदेश के 28 भाजपा सांसदों को वित्त मंत्री की नसीहत

तरुण भनोत ने प्रदेश के 28 भाजपा सांसदों को नसीहत दी है कि वे राजनीति करने की बजाय केन्द्र को सेंट्रल पूल का गेहूं लेने के लिए समझाएं ताकि किसानों का भला हो सके। हालांकि वित्तमंत्री तरुण भनोत ने किसानों को वादे के मुताबिक बोनस देने के लिए उचित कदम उठाने की बात की है। केन्द्र बनाम राज्य की लड़ाई दिनोंदिन बढ़ रही है। अब चाहे किसानों के बोनस की बात हो या फिर डेमोंस्ट्रेशन शेवर के साढ़े 14 हजार करोड़ न मिलने की बात। यह लड़ाई सियासी जरूर हो लेकिन आम जनता की कमर तोड़ रही है।

केन्द्र ने 67 लाख मीट्रिक टन गेहूं लेने पर जताई थी सहमति

राज्य सरकार की लगातार कोशिशों के बाद केन्द्र ने 67 लाख मीट्रिक टन गेहूं लेने पर तो सहमति जता दी लेकिन सात लाख मीट्रिक टन सेंट्रल पूल में लेने से इंकार कर दिया। अब राज्य सरकार की चिंता ये है कि अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं लेती है तो इसकी खरीदी का पूरा वित्तीय भार राज्य के ऊपर आ जाएगा। ये राशि गेहूं नीलाम करने के बाद पांच-छह सौ करोड़ रुपए से कम नहीं होगी और मौजूदा वित्तीय स्थिति में राज्य सरकार इस बोझ को उठाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में प्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोत ने भी केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है।

शैतान ने पत्नी प्रेमलता को भी बना दिया शैतान और गौरव के नाम को भी कर दिया कलंकित

शैतान की शैतानियत और रूपयों का मायाजाल...

मामला: एसडीएम की जांच व उससे बाद टूटी बाउंड्रीवॉल का

माही की गूंज, झाबुआ/बामनिया।

कोई व्यक्ति माया के मोह में इतना अंधा हो जाता है कि, वह माया के लोभ में अपने-आप को इस कलयुग का भगवान मान लेता है तथा अपनी मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा सभी रुपयों के बल पर ही पाना चाहता है। उसी रुपयों के बल पर सभी को खरीदकर अपने अनुरूप सभी कार्य करवा लेने की गौरोवक्ति भी करता है। ऐसा व्यक्ति अपने साथ-साथ अपनी पत्नी एवं बच्चों को भी उस माया के जाल में ऐसा मंत्र मोह देता है कि, सब कुछ 'बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया' कहावत को चरितार्थ करने में कोई चूक नहीं करता।

कुछ ऐसा ही मामला पेटलावद जनपद की बामनिया ग्राम पंचायत के खवासा एवं नारेला मार्ग की त्रिकोणीय भूखंड पर बनी अग्रवाल कॉलोनी के साथ देखा जा सकता है। उक्त कॉलोनी के भूखंड मालिक शैतान अग्रवाल जिन्होंने अपने नाम के अनुरूप अपनी माया रूपी शैतानियत दिखाकर खवासा-नारेला मार्ग की त्रिकोणीय भूमि सर्वे नंबर 66/1 को मात्र 2 लाख रुपए में अपनी पत्नी प्रेमलता व पुत्र गौरव के नाम करवाकर अपना षडयंत्र रूपी मायाजाल ऐसा रचा कि, शैतान अग्रवाल पत्नी प्रेमलता जो कि, परिवार में सरल स्वभाव की होकर अपने प्रेम रूपी व्यवहार से पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने वाली प्रेमलता को भी कानूनी दांवपेंच व फर्जी कॉलोनी का शैतान बना दिया। तो वहीं पुत्र गौरव जिसे ऐसे फर्जी कामों से दूर रखकर सही कार्य करवाया जाता तो शायद उसकी काबिलियत के अनुसार अपने नाम के अनुरूप ही गौरव क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करता। परंतु शैतान ने अपने माया रूपी शैतानियां के चलते अपने पुत्र गौरव के नाम को भी फर्जी अग्रवाल कॉलोनी में कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शैतान ने अपनी पत्नी व पुत्र के नाम से भूखंड कर परिवर्तित भूमि पर अग्रवाल कॉलोनी को विधि सम्मत एवं पूर्ण सुविधा युक्त बाउंड्रीवॉल के साथ अग्रवाल कॉलोनी में करीब 90 प्लाट काटकर नक्शे के साथ एग्रीमेंट कर कुछ प्लाट बेचकर, फर्जी रूप से लोगों के साथ जालसाजी कर अपनी शैतानियत दिखाई।

3 वर्ष के बाद भी माया के जाल में फंसे अधिकारी

शैतान की शैतानियत की शिकायतें, उसकी पत्नी एवं पुत्र के नाम से पंचायत, एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक हुई तो, शैतान ने अपनी पत्नी व पुत्र के नाम के साथ भावनात्मक ब्लैकमेल के साथ अधिकारियों को मोटी रकम दे देकर पंचायत, पटवारी, एसडीएम व कलेक्टर कार्यालय तक के अधिकारियों से अपने अनुरूप झूठी जानकारी बनवा-बनवाकर कानून का मखौल भी उड़ाने में कोई चूक नहीं की और 3 वर्ष बाद भी अधिकारी शैतान की शैतानियत व उसके मायाजाल में आकर कार्य कर रहे हैं।

26 दिसंबर 2019 को अग्रवाल कॉलोनी का औचक जांच निरीक्षण करने हेतु पेटलावद एसडीएम, पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के साथ मौके पर पहुंचे थे। पूरी कॉलोनी का निरीक्षण करके रवाना हो गए। उक्त निरीक्षण के बाद सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि, उक्त कॉलोनी की कुछ फीट पर बाउंड्रीवॉल बनाई गई थी और पटवारी ने अपने एक पंचनामे में कॉलोनाइजर लाइसेंस को छोड़ सर्वसुविधा युक्त उक्त अग्रवाल कॉलोनी को जांच पंचनामा में बताया था। साथ ही पटवारी पंचनामे में यह भी उल्लेख किया था कि, बाउंड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर है। पटवारी की जांच पंचनामे में कुछ फीट बनी बाउंड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है बताया था। वह बाउंड्रीवाल 26 दिसंबर को औचक निरीक्षण करने अपने दल के साथ एसडीएम साहब के पहुंचने तक वह अधूरी बाउंड्रीवाल बनी हुई थी। परंतु साहब के निरीक्षण कर के जाने के कुछ दिन बाद ही उस अधूरी बाउंड्रीवाल को तोड़कर शैतान ने अपनी शैतानियत का परिचय देकर अपने आप को माया रूपी कलयुगी भगवान सिद्ध कर दिया।

नगर में यह चर्चा चल रही है कि, निरीक्षण पर आए एसडीएम साहब से इस बार फिर शैतान ने अपने पुत्र के साथ जाकर बड़ी रकम देकर, ऐसा सेट कर दिया कि, वह अब अग्रवाल कॉलोनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही तो क्या यहां आकर भी नहीं देखेंगे? और वहीं दूसरी और चर्चा है कि, शैतान ने अधिकारियों को अपने माया रूपी जाल में फंसा कर क्षेत्र में अपने प्रभाव का प्रदर्शन कर रहा है।

शैतान की शैतानियत और रूपयो का मायाजाल... निरंतर... भाग-04

फाइल फोटो, 26 दिशम्बर 2019 का जब एसडीएम साहब निरक्षण करने आए, पर अब यह भी एसडीएम से सांठ-गांठ कर तोड़ दी गई बाउंड्रीवाल। सुविधा विहीन व बिना बाउंड्रीवाल की फर्जी अग्रवाल कालोनी

निसार रंभापुरी ने दिल्ली में दो स्थानों पर किया काव्यपाठ

माही की गूंज, मेघनगर। क्षेत्र सहित जिले व प्रदेश में राष्ट्रीयता कविता के जरिये तेजी से आगे बढ़ रहे निसार पठान रंभापुरी ने 29 फरवरी को अंबेडकर शोध संस्थान सभागार में भगत होस्पीटल के संचालक डॉ. सीएम भगत की पुस्तक अभिव्यक्ति के लोकार्पण व राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में काव्यपाठ किया। प्रेरणा साहित्य सांस्कृतिक मंच के बैनर तले उक्त कवि सम्मेलन में पठान ने तिरंगे में लिपट कर क्यूं पापा आए है, से अच्छी छाप छोड़ी। कार्यक्रम संयोजक मनोज शास्वत नईदिल्ली, कवियित्री सुश्री सरिता जैन, राजस्थान उदयपुर के नरेन्द्र पाल जैन आदि कवियों ने काव्य पाठ किया। अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय कवियित्री डॉ. कीर्ति काले ने की। लोकार्पण अवसर पर बतौर अतिथि साहित्यकार बाल स्वरूप रही व प्रख्यात शायर मंगल नसीम भी उपस्थित रहे।

1 मार्च को भी पठान ने चांदनी चौक दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी के आयोजन में प्रख्यात कवि शैल भदावरी के पुस्तक विमोचन 'भौला की भौकाल' में बतौर अतिथि सहभागिता की। यहां भी काव्य पाठ कर 'मेरे सर पर आजाद की माटी का कर्ज है, सर कटेगा किंतू झुकेगा नहीं से दिल्ली में झाबुआ की छाप छोड़ी। उक्त कवि सम्मेलन में हरियाणा के सतीश शास्वत, नोएडा के डॉ. सत्येन्द्र सत्यार्थी, चंद्रमणि मणिका, पवन पागल आदि ने भी काव्यपाठ किया। उक्त उपलब्धी पर क्षेत्रवासियों व साहित्य प्रेमियों सहित विधायक वीरसिंह भूरिया, समाजसेवी सुरेशचंद्र जैन आदि ने हर्ष व्यक्त किया।

संस्कृत के पर्चे से हुई 10वीं की परीक्षा की शुरूआत

माही की गूंज, मेघनगर। बोर्ड परीक्षा की शुरूआत दो मार्च से हो चुकी है। दसवीं बोर्ड की परीक्षा का पहला पर्चा 3 मार्च को संपन्न हुआ। संस्कृत का पर्चा सरल होने से परीक्षार्थियों के चेहरे पर जहां मुस्कान झलक रही थी। वहीं परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी मुस्तेद है। सभी आठ परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जवान तैनात है। पर्यवेक्षक स्थानीय स्कूल की जगह समीपस्थ के है। वहीं केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष भी अन्यत स्कूल के व्याख्यता, प्राचार्य को बनाया गया है।

मेघनगर शहर में दो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण संपूर्ण हो रही है। दसवीं में पहले दिन कन्या उमावि परीक्षा केंद्र पर 178 मे से 158 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। 20 अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्राध्यक्ष मॉडल स्कूल पेटलावद के हीरजी निनामा व सहायक केंद्राध्यक्ष नौगांवा की चेतना मोड़ के अनुसार पांच कक्षों में 11 पर्यवेक्षक अनुशासनबद्ध परीक्षा संपन्न कराने में सहयोगी रहे। शा. उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र पर नौगांवा उमावि की व्याख्याता श्रीमती आशा कौल केंद्र पर तैनात थी, सहायक केंद्राध्यक्ष श्रीमती गायत्री अलावा के मुताबिक संस्कृत के पर्चे में पांच परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दर्ज 143 मे से 138 ने परीक्षा दी। एसडीएम पराग जैन व टीआई कौशल्या चौहान भी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर कानून व्यवस्था संपन्न कराने में सक्रिय है। डीजे प्रतिबंध है। वहीं बच्चों को तनाव मुक्त रहने व परीक्षा के मद्देनजर खान-पान में भी संयमित रहने की टिप्स दे रहे है।

बलराम पाटीदार हुए सम्मानित

माही की गूंज, सारंगी। कृषि विभाग द्वारा दो दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को विभिन्न तकनीकी जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा दी गई। इस अवसर पर मेला स्थल पर स्टाल लगाए गए थे। जिसमें सारंगी के उन्नत किसान बालाराम पाटीदार द्वारा भी स्टॉल लगाया गया था। जिसे जिले में तृतीय पुरस्कार मिला। मेले में अन्य विभागों ने भी किसानों को उच्च तकनीक के बारे में भी बताया। शुक्रवार को मेले का समापन हुआ। कार्यक्रम को कलेक्टर प्रबल सिपाह, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण अतुलकर, पेटलावद विधायक वालसिंह मेड़ा, रूपसिंह डामोर, डॉ विक्रांत भूरिया, एनएस रावत ने संबोधित किया। इस अवसर पर आत्मा परियोजना के संचालक जीएस द्विवेदी ने मेले के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कृषि मेले में निजी संस्थाओं, शासकीय विभागों, अशासकीय संगठनों व मानव कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेले में लगाए गए सभी स्टालों का मूल्यांकन जिला स्तरीय गठित मूल्यांकन दल ने किया। मूल्यांकन पश्चात प्रथम पुरस्कार उद्यानिकी विभाग वन तथा अनुसंधान झाबुआ को, द्वितीय पुरस्कार कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के बालाराम पाटीदार सारंगी तथा तृतीय पुरस्कार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्नत किसान बालाराम पाटीदार नई तकनीक अपनाकर कृषि करते हैं। पाटीदार कृषि के अंतर्गत विदेश यात्रा भी कर चुके हैं और वहां पर भी सम्मानित हो चुके हैं। झाबुआ में पुरस्कार से सम्मानित होने पर सारंगी क्षेत्र के सभी किसान भाइयों ग्राम के सभी नागरिकों ने बालाराम पाटीदार को बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की।

थांदला का भगोरिया रहा फीका, राजनीतिक दलों ने निकाली गैर, व्यापार भी रहा कमजोर

माही की गूंज,थांदला। मुकेश भट्ट

आदिवासी अंचल का लोकपर्व भगोरिया उल्लास के साथ मनाया गया। परंतु पहला भगोरिया होने से भीड़ अपेक्षाकृत कम रही। तो वहीं दोनों राजनीतिक दलों ने गैर भी निकाली। जिसमें भी बीते वर्षों के मुकाबले फीकापन नजर आया। जहां पिछले वर्ष जयस ने भी गैर निकाली थी, तो वहीं इस वर्ष उसकी अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही। व्यापारियों ने बताया कि भगोरिये में जिस तरह का व्यापार चलना चाहिए, वह भी कमजोर रहा। हालांकि होली के दो दिन पहले व्यापार के बढ़ाने की प्रबल संभावना है। कांग्रेस की गैर का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष गेंदाल डामोर ने किया तो वहीं गैर के पुरानी मंडी में पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया पहुंचे। परंतु विधायक वीरसिंह भूरिया का नहीं आना कई चर्चाओं को जन्म दे गया। कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय कृषि उपज मंडी थांदला से विशाल गैर नगर के प्रमुख बाजार से होती हुई निकाली गई। तत्पश्चात ढोल मांदल ने अपनी प्रस्तुति दी। कांग्रेस की गैर में नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनीष बघेल, युवा नेता जसवंत भाबोर, कांग्रेस प्रवक्ता विकास रावत, कालूसिंह नलवाया, युवा नेता राजेश गेंदाल डामोर, चौनसिंह डामोर, पूर्व मंडी अध्यक्ष फतेसिंह नायक, पार्षद कादर शेख,आनंद चौहान, कमालुद्दीन शेख, पूर्व पार्षद अक्षय भट्ट, सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो वहीं जनजातीय विकास मंच के बैनर तले भाजपा ने भी अपनी गैर निकाली। जिस पर सत्ता के न होने का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। पूर्व विधायक कलसिंह भाभर, नपाध्यक्ष बंटी डामर, जिला पंचायत सदस्य राजेश वसुनिया सहित कई भाजपाई नेता शामिल हुए। इसके साथ ही अटल सामाजिक सेवा संस्थान के राजू धानक, जवसिंह परमार, तानसिंह मैडा आदि ने मांदल बजाकर भगोरिये का आनंद लिया।

निखिल जोशी बना क्लास में टॉपर

माही की गूंज, सारंगी। सारंगी गांव के भोपाल में अध्ययनरत निखिल यज्ञ दत्त जोशी ने शारदा विहार स्कूल भोपाल में पढ़ाई करते हुए नौवीं क्लास में 83 प्रतिशत अंक लाकर शारदा विहार स्कूल भोपाल व सारंगी गांव का नाम रोशन किया। निखिल पढ़ाई के अलावा खेलकूद में भी अग्रसर है। निखिल जोशी के स्कूल में टॉपर बनने पर सारंगी गांव में खुशी की लहर है। निखिल जोशी के टॉपर बनने पर गांव के नागरिकों के अलावा सारंगी पत्रकार संघ, श्री गणेश सुंदरकांड मंडल, साईं मित्र मंडल, महाकाल ग्रुप ने निखिल जोशी को बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

थाने की भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश, एक लाख रुपए का अर्थदंड

माही की गूंज, पेटलावद। पिछले कई दिनों से नगर में अतिक्रमण और भू-माफिया के विरूद्ध चली सरकार की मुहिम के दौरान अधिकारियों की भू-माफिया और बड़े अतिक्रमणकर्ताओं से मिलीभगत के गंभीर के आरोप लग रहे थे। थाना पेटलावद को आंवटित भूमि पर दबंग बरबेटा का कब्जे का मामला सामने आया था। लेकिन प्रशासन ने यहां अपनी अतिक्रमण में चली देखते ही हटाओ की नीति में परिवर्तन कर अतिक्रमणकर्ता को अपने दस्तावेज पेश करने का पूरा मौका दिया है। मामले में रोज नए-नए आंकडें लेन-देन और सेटिंग सामने आ रहे थे। वहीं थाने की भूमि के सीमाकंन का आवेदन देने वाले पूर्व थाना प्रभारी शर्मा के स्थानांतरण को भी भू-माफिआओं से जोड़ा जा रहा था। लेकिन थाना प्रभारी की रवानगी के चार दिन बाद ही तहसील न्यायालय ने थाने की करोड़ों की बेशकीमती भूमि पर बरबेटा का अवैध रूप से कब्जा होना स्वीकार करते हुए अतिक्रमण हटाने और एक लाख रूपये अर्थदंड का लगाया गया। न्यायालय के आदेशों के बाद उस दावे कि भी हवा निकल गई जिसमें ये कहा जा रहा था थाना प्रभारी दिनेश शर्मा को भु-माफिया ने प्रशासन और सरकार से सेटिंग कर हटवाया है क्योंकि थाना प्रभारी के जाने के बाद भी निर्णय अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध ही आया हैं। न्यायालय द्वारा अतिक्रमणकर्ता बरबेटा को दो दिन अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन अतिक्रमणकर्ता मामले को अब न्यायालय में ले गया है। जिससे अतिक्रमण हटना लम्बे समय के लिये टल सकता हैं। यदि प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुहिम की तरह बड़े भू-माफिआओं के खिलाफभी मुहिम चलाकर तुरंत कब्जा हटाया जाता तो आज करोडों की भूमि सरकार के कब्जे में होती और बदमानी भी नहीं झेलना पडती ।

सहकारिता माफिया गणेश प्रजापत को भेजा जेल

माही की गूंज, झाबुआ। सहकारिता विभाग छापामार कार्रवाई के दौरान गणेश प्रजापत ने महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स को छिपाकर भागने का प्रयास करते हुए शासकीय कर्मचारियों से छीना-झपटी की थी। इसको लेकर मेघनगर थाने में आईपीसी धारा 353 शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा गणेश प्रजापत के विरुद्ध 22 फरवरी को दर्ज हुआ था। एफआईआर के बाद आरोपित गणेश प्रजापत लगातार फरार चल रहा था। मंगलवार को गणेश प्रजापत मेघनगर थाने में सरेंडर करके गिरफ्तारी दी। इसके बाद गणेश को थांदला न्यायालय में पेश किया गया। शासकीय कार्य में बाधा को देखते हुए न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को विचार करने के लिए 2 दिन का समय लेते हुए जेल वारंट जारी किया गया। इसके बाद गणेश प्रजापत को जेल भेज दिया गया।

चोरों के हाथ में थमा रहे जांच का उस्तरा

भ्रष्टों द्वारा धमकी देने पर सुरक्ष करवाई मुहैया पर भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं!

माही की गूंज, खवासा। उमेश मालवीय

प्रशासन, जिलेवासियों को अपनी अनियमितता व कारनामे के साथ हम किस स्तर तक के भ्रष्टाचारी है, वो जिले का प्रशासनिक अमला नित नए तरीकों से दिखा रहा है। कमलनाथ सरकार सुशासन का दावा एवं भ्रष्टाचारियों को नस्तेनाबूद करने की बात भले ही कर रही हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार की कही बात जिले में प्रशासनिक कार्य व्यवस्था को देख हास्यप्रद ही बन रही है।

ऐसे कई भ्रष्टाचार जिले में हुए हैं। जिनका खुलासा आमजन के साथ मीडिया के सामने भी नहीं आया होगा पर जहां भ्रष्टों के कारनामे सार्वजनिक हो और जनहित में आम लोग उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े होकर कार्यवाही करने की मांग करें तो भी, भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की स्थाई सांठ-गांठ के चलते आमजन व मीडिया तक को प्रशासन गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ता हैं। वहीं अधिकारी जांच के नाम पर लीपापोती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो तय है जहां जिस पंचायत या अंतिम छोर तक जहां कोई इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, इनके आंतक के चलते उनके काले कारनामों के खिलाफकोई बोलते ही नहीं है, वहां पर किस स्तर तक का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

थांदला ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुकड़ीपाड़ा की ही बात करें, तो यहां एक शिक्षित एवं गांव की बेटी ने अधिकारियों की मिलीभगत के साथ सरपंच-सचिव ने मछली फंटा से मंगलिया नानूराम के घर तक सीसी मार्ग के नाम पर पूरे 12 लाख 96 हजार बिना सीसी मार्ग बनाए ही राशि आहरण कर ली। इसकी शिकायत 21 जनवरी को जनसुनवाई में की थी। शिकायत के बाद अधिकारी मामले को गोल-मोल कर लीपापोती करने में लग गए, तो शिकायतकर्ता रेखा निनामा ने अधिकारियों पर कार्यवाही हेतु सोशल मीडिया एवं टेलीफोन पर अपना दबाव जनहित के लिए बनाया। जिसके बाद प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियो से संरक्षण प्राप्त सरपंच-सचिव ने अपने परिजन के माध्यम से टेलीफोन कर जान से मारने एवं अश्लील गालियों के साथ धमकियां दी। सरपंच-सचिव के उक्त कृत्य और शिकायत के मामले में आगे और कार्यवाही हेतु अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं बनाया जाए कि मंशा के साथ धमकाने का काम भी किया गया। बिना निर्माण सड़क मार्ग में भ्रष्टाचार से लेकर धमकाने तक का मामला मीडिया में सार्वजनिक भी हुआ। खासकर उक्त पूरे मामले में माही की गूंज ने प्रमुखता से भ्रष्टों की कारस्तानियों के समाचार प्रकाशित किए। लेकिन शिकायत एवं अखबार में छपने वाले समाचार अधिकारियों की चांदी काटने का जरिया बन चुके है और जितना मामला ज्यादा उजागर होता है। जिले के अधिकारी भ्रष्टाचार की लीपापोती करने के लिए उतनी ही ज्यादा चांदी काटते है।

27 फरवरी की कलेक्टेट में रेखा निनामा ग्रमीणों के साथ जाकर अधिकारियों की कारस्तानियों के नाम दिया ज्ञापन।

पंचायत के भ्रष्टों के खिलाफ सब कुछ मामला सार्वजनिक होने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों ने कोई भी कार्यवाही भ्रष्ट सरपंच-सचिव के विरुद्ध नहीं की। परंतु कार्यवाही हेतु अधिकारियों पर दबाव बनाने के कारण रेखा निनामा को मिली धमकी के बाद पुलिस को रेखा निनामा द्वारा 13 फरवरी को की गई शिकायत क्रमांक 1171 पर ग्राम पंचायत कुकड़ीपाड़ा द्वारा निर्माण कार्य में की गई अनियमितता की शिकायत करने के परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत सरपंच-सचिव के समर्थकों द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के कारण व्हीसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 के तहत सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की गई थी। जिस पर पुलिस कप्तान विनीत जैन ने 28 फरवरी को पत्र क्रमांकध्जीविशा.ध्झा.ध्2020-(32ब) के माध्यम से थांदला एसडीओपी को आदेशित किया कि, कुमारी रेखा पिता भूरजी निनामा (28) निवासी ग्राम कुकड़ीपाड़ा को उसके गृह ग्राम आगमन के दौरान एक जवान की ड्यूटी सुरक्षा हेतु लगाना सुनिश्चित करें एवं कुमारी रेखा के संपर्क में रहे, ताकि उसके गृह ग्राम आगमन पर सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। इस संबंध में एसपी जैन ने आदेशित कर सुरक्षा मुहैया करवाई गई।

रेखा निनामा इंदौर में रहकर पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही है। गूंज में 20 फरवरी को ÷जांच के नाम पर चोर के हाथ में थमा दिया उस्तरा'', ÷जनचर्चाः सीईओ द्वारा मांगी गई रिश्वत मिलने पर मिल रहा भ्रष्टों को संरक्षण'' शीर्षक के साथ प्रकाशित हुए समाचार के बाद 27 फरवरी को रेखा निनामा कुछ ग्रामीणों के साथ कलेक्टर ऑफिस में जाकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर संदेह जताते हुए मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। जिसमें बताया कि, सरपंच-सचिव के भ्रष्टाचार की शिकायत 21 जनवरी को जनसुनवाई में की, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की। अधिकारीयो ने मौके पर वस्तु स्थिति जानी। जहां धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ, बावजूद अधिकारियों द्वारा मीडिया व आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि, वह रोड परिवर्तित कर रासु मेहजी के मकान से मूलचंद रावजी के घर तक सीसी रोड बना दिया गया है, जबकि वह सीसी रोड 14 लाख 88 हजार का अलग से मंजूर है। तो वही दीपा फलिया के घर से जालू के घर तक 4 लाख 35 हजार रुपए का मार्ग मंजूर हुआ वह भी रोड सरपंच-सचिव ने नहीं बनाया। उक्त शिकायत व ज्ञापन के बाद धमकी मिलने पर सुरक्षा मुहैया तो करवा दी गई, परन्तु भ्रष्टाचारियो के खिलाप कोई ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं की गई।

भ्रष्टों की कारस्तानी: 14 लाख 88 हजार व 12 लाख 96 हजार की हकीकत। निरंतर...

सात साल से लटकी पड़ी पानी की टंकी

घटिया निर्माण से जगह-जगह फुटी पाईप लाइन

माही की गूंज, पेटलावद। विकासखण्ड के ग्राम मठमठ में शासन द्वारा पेज जल व्ययस्था हेतु लगभग 27 लाख रूपए की लागत की पानी की टंकी और पूरी पंचायत में पाईप लाइन बिछाकर पानी पहुंचाने की योजना सात वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी। उक्त कार्य को पीएचई विभाग की देख रेख में पूर्ण किया जाना था, लेकिन योजना के स्वीकृत होने के सात वर्ष बाद भी आलम ये है कि उक्त योजना में बनी टंकी तक ग्राम पंचायत के हेडओवर नहीं हो सकी है, न ही मठमठ ग्राम पंचायत के लोगों तक पाईप लाईन के माध्यम से पानी पहुंच सका है। एक के बाद एक सात गर्मी निकल चुकी है, लेकिन मठमठ के ग्रामीणों की पीने के पानी की समस्या जस की तस है। विभाग की देख रेख में कार्य में इतनी लापरवाही कि गई की गांव में डाली गई पाईप लाईन जगह जगह से फुट गई है और पानी की टंकी तक लिकेज हो गई हैं। अब पीएचई विभाग के अधिकारी ऐसी जर्जर स्थिति में पानी की टंकी ग्राम पंचायत के हैंडओवर करने के लिए दबाब बना रहें है। वही ग्राम पंचायत ऐसी स्थिति में पानी की टंकी अपने अधीन करने को तैयार नहीं है। उक्त मामले ग्राम पंचायत सरपंच नानुराम भूरिया का कहना है कि पानी की टंकी लिकेज है। पाइप लाइन जगह जगह से फुट चुकी है। जब तक विभाग पुरा कार्य सही से करके नही देता हम टंकी का हैंडओवर नही लेंगे। मामले की शिकायत मठमठ निवासी महेश पोरवाल द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर दिसम्बर 2019 से कर रखी है। शिकायत क्रंमाक 9796886 मिले लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। उलटा विभाग शिकायककर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाब बनाया जा रहा हैं। वही पीएचई विभाग के एसडीओ बघेल का कहना है कि हमारे द्वारा वर्क पूरा कर ग्राम पंचायत को योजना संचालन के लिए दे दी गई थी, लेकिन पंचायत द्वारा संचालन नहीं किया, इसलिए देखरेख के अभाव में लाईन फुट गई। जिसे हमारे द्वारा एक बार रिपेयर भी करवा दिया गया है। विभाग की गलती ये है ग्राम पंचायत से हैंडओवर का लिखित लेटर नहीं लिया गया। विभाग की ओर से अब कहा जा रहा है कि उक्त योजना को जल मिशन योजना में भेजा गया है। जल्द स्वीकृति मिलने पर मरम्मत कर पूरी योजना पंचायत के हैंड ओवर कर दी जाएगी। ग्राम पंचायत और पीएचई के बीच उलझी लाखों की योजना भ्रष्टाचार और देख रेख के अभाव में जर्जर हालत में बिना सुविधा का लाभ लिए पहुंच गई है। सात साल बाद भी मठमठ के ग्रामीण पानी की टंकी की और आशा भरी निगाहों से दखते है। एक दिन यहां से ग्रामवासियों को सुचारू रुप से पानी मिल पाएगा और पीने

संपादकीय

इंसानियत और भाईचारे को जिंदा रखने वाले 'शांतिदूतों' को सलाम

देश की राजधानी दिल्ली अब शांत लगती है। कमोबेश ऊपरी तौर पर ऐसा माना जा सकता है। जिंदगी भी अब पटरी पर लौटती दिखाई देती है, लेकिन आगजनी की कालिखें साफ होने में वक्त लगेगा। जानलेवा हमलों के जख्म भी भरने में वक्त लगेगा। दंगा और हिंसा से प्रभावित इलाकों की मेनरोड पर पुलिस और सुरक्षा बलों के सशस्त्र दस्ते फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आम आदमी का खौफऔर भीतरी दहशत को खुरचने के प्रयास जारी हैं। दुकानें खुलवाई गईं, सड़कें खोली गईं, खरीददारी शुरू हुई है और अपने-अपने काम पर लौटने के आह्वान भी किए गए हैं, लेकिन गलियों के अंदर की हकीकतें बहुत भिन्न हैं। चांदबाग की कुछ गलियों में लगभग सभी मकानों पर ताले लटके हैं। लोग या तो पलायन कर गए हैं अथवा दंगे के हालात के मद्देनजर कहीं और चले गए हैं। एक सुखद यथार्थ जरूर सामने आया है, जिसने धर्म और मजहब, हिंदू-मुसलमान के दरमियान भाईचारे, इनसानियत और भरोसे को जिंदा रखा है। ऐसे चेहरे हमें 'शांतिदूत' ही नहीं, बल्कि 'फरिश्ते' लगे। इस आलेख के लेखक ने बुधवार और गुरुवार को कई घंटे हिंसा प्रभावित इलाकों में गुजारे। उस दौरान अचानक ही चार मुस्लिम युवा मिले। उन्होंने बताया कि गलियों में अंधेरा करके खास वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। दंगाई 'जय श्रीराम' के नारे लगाते हैं और मुल्लों के बचे हुए घर पूछने लगते हैं। एक ने घबराते हुए आशंका व्यक्त की कि उसने रमजान के महीने के लिए अपनी दुकान में करीब 50 लाख रुपए का सामान जमा किया है। यदि दंगाइयों ने उसे जला दिया, तो फिर क्या होगा? लेकिन उन चारों का साझा शुक्रिया यह है कि यदि वे आज जिंदा हैं, तो पड़ोस में हिंदू परिवारों के कारण3! एक अन्य उदाहरण दूसरे मुसलमान का है। वह दूध लेने बाजार गया था। पीछे से बेटे का फोन आया कि दंगाई घर में घुस रहे हैं और आग भी लगा दी है। मुस्लिम ने घर के पास जाकर देखा तो मंजर तबाही का था, लेकिन उन पलों में हिंदुओं ने उसे घर की तरफजाने से रोका। साफ था कि यदि वह भी उधर जाता तो मौत निश्चित थी। उसकी पत्नी और बच्चे तो छत पर चले गए, लेकिन 85 साल की मां अकबरी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकी और जिंदा जलकर भस्म हो गई। उसका चीखता हुआ शोक मुसलमान परिवार के साथ हिंदुओं ने भी मनाया। सरदार जिंदर सिंह सिद्धू ने जियाउद्दीन को लठैत दंगेबाजों से बचाया और अपने घर ले आए। खून ज्यादा न बहे, लिहाजा अपनी पगड़ी से ही पट्टी का काम लिया और उसे जिया के सिर पर बांध दिया। इसी तरह सलमान सिद्दिकी ने कोमल शर्मा को बचाया। अशोक नगर में हिंदुओं ने मस्जिद को आग नहीं लगने दी, तो चांदबाग में मुसलमानों ने 3 हिंदू मंदिरों की रक्षा की और उपद्रवी उन्हें छू तक नहीं सके। ऐसे कई उदाहरण होंगे। अब तो विशेष जांच टीम अतिरिक्त आयुक्त, अपराध की अध्यक्षता में गठित कर दी गई है। अलग-अलग डीसीपी के नेतृत्व में दो टीमें जांच करेंगी। जिज्ञासा के साथ सवाल भी है कि क्या हिंसा के शैतानों और दरिंदों को सजा मिल सकेगी? क्या जांच उस गहराई और साजिश तक पहुंच सकेगी कि विभिन्न हथियार, पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब की थैलियां और अंततः पिस्तौल या रिवॉल्वर कहां से आए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जांच 15-20 साल तक चलती रहे, फिर सरकारें बदल जाएं, तो जांच की दिशा भी बदल जाए और तब तक किसी नए दंगे, नई साजिश की हकीकत सामने आ जाए? अच्छी खबर यह है कि इधर आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या और दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज होता है और उधर मुख्यमंत्री केजरीवाल उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देते हैं। अब दायित्व पुलिस जांच और अदालत का है कि ऐसे मामलों को निर्णायक निष्कर्ष तक पहुंचाएं। दंगे सिर्फ अपराध ही नहीं हैं, बल्कि इन्सानियत पर कलंक भी हैं। इन धब्बों को मिटाया जाना चाहिए।

एक सलाह

समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो।

काम की बात

बड़ा आदमी वो है जोअपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे।

बढ़ती सांप्रदायिक राजनीति

प्रो. एनके सिंह
अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार

जब डोनाल्ड ट्रंप भारत की महत्त्वपूर्ण यात्रा कर रहे थे तथा उनकी पत्नी मेलानिया दिल्ली में हैप्पीनैस क्सासिज को पढ़ा रही थीं, इसी बीच सांप्रदायिक राजनीति के कारण राष्ट्रीय राजधानी में दंगों में 10 लोग मारे गए। चूंकि भीषण राजनीतिक गतिविधियों का युग शुरू हो चुका है, राजनीति में चीजों को सांप्रदायिक नजरिए से देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। शायद भारतीय राजनीति के लिए हमेशा सांप्रदायिक दृष्टिकोण था, जैसे कि स्वतंत्रता के लिए उनकी लड़ाई मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग तथा गांधी के ईश्वर-अल्लाह दर्शन के साथ जज्ब होने से ऊपर नहीं थी। उस समय कुछ हिंदू संगठनों के साथ-साथ मुस्लिम संगठन भी सक्रिय रहे, परंतु वे छोटे थे तथा उनका कम प्रभाव था। भारतीय जनसंघ ने अपना सिर उठाना शुरू किया, किंतु उसके अस्तित्व की अनदेखी जारी रही। मुसलमानों का भी ऐसा ही मामला था, तब तक जब तक जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कांग्रेस के खिलाफसशक्त बनाना जारी रखा। समाजवादी व कम्युनिस्ट भी यहां थे, किंतु उनके बड़े नेताओं, जैसे कि कम्युनिस्ट डेंग अथवा नंबूद्रीपाद तथा जयप्रकाश व लोहिया जैसे समाजवादियों ने स्वतंत्रता तक अपने दलों का नेतृत्व किया। भारत के विभाजन के साथ देश की स्वतंत्रता देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। इसके न केवल राजनीति पर, बल्कि देश के संपूर्ण सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रलयात्मक प्रभाव पड़े।

यह एक बड़ा सांप्रदायिक विभाजन था, किंतु कांग्रेस ने इस परिणाम को भारत में हिंदुओं तथा मुसलमानों की स्थिति की व्याख्या के बिना तथा पाकिस्तान को इस्लामी राज्य बनाने की स्वीकृति देकर भारत को भारत ही बने रहने का दर्जा देकर भ्रांतिपूर्ण बना दिया। भारत, भारत ही बना रहा, इसकी चारित्रिक विशेषताएं इंगित करने के लिए किसी धर्म विशेष को तवज्जो नहीं दी गई, किंतु जैसा कि सरदार पटेल ने कहा, कई मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हुए तथा हमने उन्हें यहां बने रहने की अनुमति दे दी। यह हिंदू बहुमत है जिसने मुस्लिम अल्पसंख्यकों का यहां बने रहना स्वीकार कर लिया। किसी ने यह उल्लेख नहीं किया कि यह पंथनिरपेक्षता के कारण था, किंतु यह बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों को इसी राज्य में बने रहने की अनुमति के कारण था। यह केवल इंदिरा गांधी थी जिन्होंने बाद में संविधान में संशोधन करते हुए पंथनिरपेक्षता के साथ-साथ समाजवाद को अधिमान दिया। स्पष्ट रूप से यह बाद का विचार था तथा इसकी परिकल्पना संविधान के निर्माताओं ने नहीं की थी। पृष्ठभूमि में चाहे जो कुछ भी घटित हुआ हो, तथ्य यह है कि एक देश से दो देश बनाए गए तथा इसका आधार धर्म था। धर्म ही क्षेत्रों के सीमांकन तथा मानचित्र में बदलाव के लिए प्रत्येक कस्बे में जनगणना करने के लिए आधार

बना। हालांकि भारत हिंदू बहुल बना रहा, किंतु यह मुसलमानों के लिए भी उपलब्ध रहा तथा बड़ी संख्या में मुसलमानों ने यहां रहने का फैसला किया। भारत के संविधान ने भी उन्हें बराबर के अधिकार दिए हैं। मुसलमानों का राजनीतिक दलों, विशेषकर कांग्रेस द्वारा वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया गया, क्योंकि उनका संयुक्त वोट था तथा वे एक साथ जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक थे। हाल ही तक, जब तक कांग्रेस का शासन रहा, हिंदू व मुसलमानों में अंतर नहीं किया जाता था तथा अल्पसंख्यकों के साथ प्राथमिकता वाला व्यवहार होता था।

इस नजरिए ने एक ही दल का शासन बनाए रखने में मदद की। बाद में असदुद्दीन औवेसी तथा कुछ अन्य मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों की उत्कृष्टता पर जोर देना शुरू किया क्योंकि उन्होंने 800 वर्षों तक भारत पर शासन किया तथा ताजमहल व अन्य विश्व विख्यात स्मारक भी उन्होंने ही बनाए। यह तर्क अजीब दिखता है क्योंकि लोकतंत्र बहुमत के सिद्धांत को स्वीकार करता है, न कि यह कि अल्पसंख्यक के रूप में किसने कितने समय शासन किया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अपना संविधान है। संविधान ने मुसलमानों को भी बराबर के अधिकार दे रखे हैं तथा यहां कानून का शासन है। दिल्ली में जामिया तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दो ऐसे संस्थान हैं जो धार्मिक अलगाववाद को खाद-पानी देने के केंद्र के रूप में उभरे हैं। मुस्लिम लॉबी की सीमाओं में आजादी की बात तथा टुकड़े-टुकड़े हिंदुस्तान की बात होने लगी है तथा इसको पंथनिरपेक्षता का चोला पहने कुछ पत्रकारों का भी समर्थन हासिल है। इसी का परिणाम है कि शाहीन बाग की तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं जहां सड़कों की अगली पंक्तियों में धरनों के लिए महिलाओं का प्रयोग हो रहा है। यह धरना अभी भी जारी है तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने तथा बातचीत चलाने व सरकार की ओर से वार्ता का निमंत्रण देने के बावजूद कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। यह एक नए प्रकार का प्रदर्शन है तथा अगर सरकार इसे रोकने के लिए बल का प्रयोग करती है तो और ज्यादा प्रदर्शनों के लिए पुख्ता आधार तैयार हो जाएगा। सच्चाई यह है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छिनती नहीं है। यह केवल गैर कानूनी रूप से देश में घुसपैठ को गैर कानूनी बनाता है तथा इस आधार पर अगर प्रदर्शन हो तो यह जायज नहीं है। यहां तक कि अगर संवैधानिक संरक्षण चाहिए तो अपीलकर्ता का नागरिक होना जरूरी है। यह विरोध प्रदर्शन और फैल सकता है तथा इसका एकमात्र कारण सांप्रदायिक राजनीति की प्रधानता है जिसे आजकल खाद-पानी दिया जा रहा है। यह देश विरोधी राजनीति है तथा सरकार को इससे निपटने के लिए नए रास्तों की तलाश करनी चाहिए। कोई सरकार कैसे 'किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है' की उक्ति को सहन कर सकती है।

तालिबान समझौताः हम क्या करें ?

डॉ. वेद प्रताप वैदिक

कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच जो समझौता हुआ है, यदि वह लागू हो सका तो दक्षिण एशिया में शांति के नए युग की शुरुआत होगी। अफगानिस्तान में जाहिरशाह के तख्ता-पलट (1973) के बाद से आज तक इतनी अस्थिरता बनी रही है कि उसके कारण पाकिस्तान, भारत और ईरान तो परेशान रहे ही हैं, आतंकवाद ने अमेरिका को भी दहला दिया था।

अफगानिस्तान से तालिबान की सत्ता खत्म की 2002 में अमेरिकी और नाटो फौजों ने लेकिन पिछले 18 साल में वे अफगानिस्तान पर काबू नहीं कर पाए। अमेरिका ने वहां अपने 3500 सिपाही खोए और अरबों-खरबों डॉलर गवां दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते वक्त वादा किया था कि वे अमेरिकी फौजों को अफगानिस्तान से हर हाल में वापस बुला लेंगे।

अब उनका सीना गर्व से फूल सकता है लेकिन जैसी कि कहावत है कि काणी के ब्याह में सौ-सौ जोखिम होती है। यह समझौता सफल हो जाए, तभी उसको सफल मानना चाहिए। पहली बात तो यह कि अभी काबुल सरकार और तालिबान के बीच समझौता होना बाकी है। यदि दोनों के बीच दंगल जारी रहता है, मतभेद रहता है तो अमेरिका के साथ हुआ समझौता बेकार हो जाएगा।

अभी तो यही नहीं पता कि काबुल में किसकी सरकार है ? अशरफगनी की या डॉ. अब्दुल्ला की ? दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। मान लें कि अमेरिकी दबाव में ये दोनों नेता अपना झगड़ा झुलझा लें तो भी क्या गारंटी है कि वे तालिबान से समझौता कर लेंगे ?आधे अफगानिस्तान पर पहले से तालिबान का कब्जा है। क्या गनी और अब्दुल्ला उन्हें आधी सत्ता सौंप देंगे ? वे आधी सत्ता स्वीकार क्यों करेंगे ? उन्हें पाकिस्तान और अमेरिका का समर्थन पहले से ही प्राप्त है। इसके अलावा तालिबान के पास अफीम की आमदनी इतनी ज्यादा है कि वे अपनी स्वतंत्र सरकार खुद चला सकते हैं।

अफगान फौज में भी पठानों की संख्या सबसे ज्यादा है। तालिबान मूलतः गिलजई पठानों का संगठन है। अमेरिकी फौजों की वापसी के 14 महिनों के दौरान तालिबान शांति कैसे बनाए रखेंगे ? उनके कई समूह अपनी मनमानी के लिए कुख्यात हैं। यह अच्छा हुआ कि भारत के विदेश सचिव इस मौके पर काबुल गए। ज्यादा अच्छा होता कि हमारे विदेश मंत्री भी दोहा में होते, जैसे कि अमेरिकी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री वहां हाजिर थे। इस समय जरुरी यह है कि भारत काबुल सरकार और तालिबान के साथ भी सीधे संपर्क बनाए रखे। तालिबान जब काबुल में सत्तारुढ़ हुए थे तो उनके नेता मुझसे काबुल, लंदन, न्यूयार्क और जर्मनी में बराबर मिलते रहते थे। हमारे अपहत जहाज को छुड़वाने में हमने उनसे मदद भी ली थी। यह सही समय है, जबकि हम पाकिस्तान से भी संवाद शुरु कर सकते हैं।

सात सालों में सबसे कम जीडीपी का स्तर

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को लेकर पिछले हफ्ते सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं, वे अर्थव्यवस्था की निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 4.7 फीसद दर्ज की गई है जो पिछले सात साल में सबसे कम है। जीडीपी का इतने न्यूनतम स्तर पर चले जाना अर्थव्यवस्था की दशा को बताने के लिए पर्याप्त है। जीडीपी का इतना गिर जाना इस बात का भी प्रमाण है कि मंदी का जो दौर दिसंबर 2018 में शुरू हुआ था, वह अभी बना हुआ है और भविष्य में भी सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के बड़े और प्रमुख क्षेत्रों में तीसरी तिमाही में कोई सुधार दिखाई नहीं दिया है। चाहे बिजली क्षेत्र हो या इस्पात क्षेत्र, उत्पादन में सबकी हालत खराब है। तीसरी तिमाही को छोड़ दें तो इस जनवरी में भी इस्पात उत्पादन में 3.26 फीसद की गिरावट आई है। तीसरी तिमाही में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, सीमेंट जैसे क्षेत्रों में उत्पादन की रफ्तार न सिर्फमंद रही, बल्कि पिछले वर्षों के मुकाबले भी इनमें भारी गिरावट का दौर रहा। यह इस बात का संकेत है कि देश की जीडीपी को बढ़ाने वाले छोटे-बड़े उद्योग सभी मंदी से बुरी से तरह प्रभावित हैं। ऐसे में जीडीपी कैसे बढ़ेगी, यह बड़ा सवाल है।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र देश की जीडीपी में बड़ी भूमिका अदा करता है। लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में वाहनों की बिक्री में 17 फीसद से ज्यादा की कमी देखने को मिली है। सेवा और कृषि क्षेत्र को छोड़ कर किसी भी क्षेत्र से उत्साहवर्धक खबर नहीं आई है। अर्थव्यवस्था की यह मंदी जहां अर्थशास्त्रियों और उद्योगों के लिए के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं सरकार इससे निश्चिंत नजर आ रही है। वित्त मंत्री का मानना है कि जीडीपी जितनी नीचे जानी थी, चली गई अब इससे और नीचे नहीं जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि अब अर्थव्यवस्था में सुधार का दौर शुरू हो रहा है। लेकिन इससे भरोसा इसलिए नहीं जगने वाला क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था में सुदार को लेकर ऐसे उम्मीदों भरे काल्पनिक दावे कई महीनों से करती आ रही है। मंदी दूर करने के तात्कालिक उपाय के तौर पर पिछले साल सरकार कारपोरेट करों में कटौती करने का बड़ा कदम उठाया था। तब कहा गया था कि इससे औद्योगिक उत्पादन जोर पकड़ेगा। लेकिन इसका नतीजा आज सबके सामने है। इस बार बजट ने भी लोगों को और उद्योगों को निराश ही किया है। प्रस्तावित बजट में ऐसे कोई उपाय नहीं किए गए हैं जो अर्थव्यवस्था को जल्द ही पटरी पर लाने में सहायक हो।

चाणक्य नीति

धर्म की व्याख्या करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति इस नीतिशास्त्र को पढ़कर ही अपने कार्यबोध यानी धर्म के प्रति जागरूक हो जाता है। उसे अच्छे-बुरे का ज्ञान हो जाता है। वह जान जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। धर्म का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ऐसा होने पर ही वह नीतिगत चल सकता है। सामान्यतः देखें तो कुछ सामान्य बातें धर्म सम्मत मानी गई है। विशेषतः ऐसा कार्य जिसके करने से श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति होती है।

समाज के तनाव में फेक न्यूज

पवन दुग्गल
साइबर कानून विशेषज्ञ

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, यानी फर्जी खबरें पहले ही कम नहीं थीं, पर दिल्ली में हुए दंगों से पहले और बाद में तो जैसे इनकी बाढ़ ही आ गई। हालात बिगाड़ने में इसकी भूमिका कमतर नहीं मानी जा रही। स्थिति यह है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं से गलत इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं हासिल कर रहा है और धड़ल्ले से उसका प्रसारण करके उसे बढ़ावा दे रहा है। मगर इसका बेजा फायदा वे लोग उठा रहे हैं, जिनका इससे स्वार्थ जुड़ा है। जाहिर है, देश और समाज फर्जी खबरों की बड़ी कीमत चुका रहे हैं। समस्या यह है कि फर्जी खबरों से निपटने के लिए हमारे पास कोई खास कानून नहीं है। फिलहाल सूचना प्रौद्योगिकी कानून (आईटी ऐक्ट) व भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) ही बतौर विकल्प उपलब्ध हैं।

फर्जी खबरों का मतलब होता है, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जब कोई इसे तैयार करता है, तो आईपीसी की धारा-469 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मगर यह प्रावधान तब लागू होता है, जब उस फर्जी खबर से किसी की मानहानि हो। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके किसी के साथ यदि धोखाधड़ी की जाती है, तो वह कहीं ज्यादा गंभीर व दंडनीय अपराध माना जाता है। तब आईपीसी की धारा-468 के तहत मामला दर्ज किया जाता है, जिसमें सात साल तक के कारावास का प्रावधान है। लेकिन बीते कुछ समय से यह देखने में आया है कि फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मामले में हमारी पुलिस अमूमन आईपीसी की धारा-468 या 469 का इस्तेमाल नहीं करती। यही कारण है कि फेक न्यूज के अपराध में शायद ही कोई जेल जाता है।

कोढ़ में खाज यह है कि फर्जी वीडियो या खबरों को प्रसारित करके लोगों को उकसाने वालों पर कानूनी प्रावधान लागू ही नहीं होता। वर्ष 2008 में आईटी ऐक्ट 66-ए के तहत लोगों को गुमराह करने वाली जानकारियों का प्रचार-प्रसार दंडनीय अपराध तय किया गया था। मगर 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल व अन्य की जनहित याचिकाओं को स्वीकार करते हुए इसे असांविधानिक घोषित कर दिया। हां, आईटी ऐक्ट 67 के तहत पुलिस जरूर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन यह प्रावधान मूलतरू अश्लील सामग्रियों के ऑनलाइन प्रकाशन-प्रसारण के संदर्भ में है।

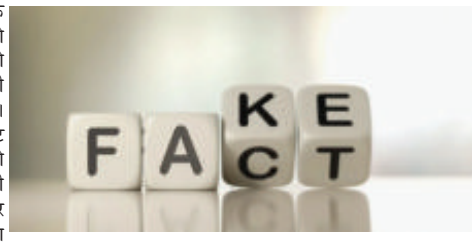

यह हालत तब है, जब 'डीप फेक' के रूप में कहीं गंभीर चुनौती अपने यहां पांव पसार चुकी है। 'डीप फेक' में तकनीक झूठ को इतना ताकतवर बना देती है कि नंगी आंखों से उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसमें किसी वीडियो में आवाज आदि बदलकर उसे इस तरह से नया रूप दिया जाता है कि आम आदमी के लिए उसे झुठलाना मुश्किल हो जाए। अव्वल तो देश में फर्जी खबरों से लड़ने के लिए कानून का अभाव है, फिर तकनीक दिनोंदिन उन्नत हो रही है, नतीजतन असामाजिक तत्व निर्भीक होकर इंटरनेट पर अपना एजेंडा चलाते हैं। देश के नीति-नियंताओं को यह संकल्प लेना होगा कि भारत को हम फेक न्यूज या डीप फेक की प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। अब इन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है।

अभी तो महज शुरुआत है। वक्त बीतने के साथ इसके इतने घिनौने रूप आएंगे कि हमारा आपसी सौहार्द खत्म हो सकता है। आदर्श स्थिति तो यह है कि इन सबको रोकने के लिए खास कानून बनाया जाए और फर्जी खबरों के प्रकाशन-प्रसारण को घिनौना दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। मलेशिया ने हाल ही में ऐसा किया है। मगर इसके साथ-साथ हमें पुलिस महकमे और अपनी न्यायपालिका की क्षमता भी बढ़ानी होगी। देश के नेतृत्व को यह एहसास होना चाहिए कि फेक न्यूज या डीप फेक ऐसा जहर है, जो आम लोगों को धीरे-धीरे जहरीला बना रहा है। दिल्ली दंगे के संदर्भ में ही असली वीडियो के साथ फर्जी वीडियो खूब प्रसारित किए गए। इन वीडियो के सहारे लोगों को जमकर उकसाया गया। अन्य संवेदनशील मामलों में भी हमने ऐसा ही देखा है।

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि विकल्पहीनता की स्थिति में इंटरनेट सेवा रोक देने के उपाय अपनाए जाते हैं। मगर यह ठोस समाधान नहीं है। बल्कि यह कदम कितना नुकसानदेह हो सकता है, मिस्र इसका उदाहरण है। वहां की सरकार ने जैसे ही इंटरनेट सेवा बंद की, 'अरब स्प्रिंग' की शुरुआत हो गई और हुकूमत का तख्ता-पलट कर दिया गया। अपने यहां तो अब जीवन जीने के मौलिक अधिकार में इंटरनेट का इस्तेमाल शामिल कर लिया गया है। ऐसे में, बहुत ज्यादा दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद रखना संभव नहीं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक जानकारी जरूर रोकी जा सकती है, मगर वह भी तब, जब देश की अखंडता, प्रभुता और सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करना आवश्यक हो, सार्वजनिक कानून-व्यवस्था को खतरा हो या फिर किसी कानून के उल्लंघन को रोकने की जरूरत पड़े। फिर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जरूरी यह भी है कि इंटरनेट बंद करते ही सरकार इसकी वजह आम लोगों के बीच प्रसारित करे।

स्पष्ट है, फर्जी खबरों को रोकने के लिए हमें विशिष्ट कानून बनाने ही होंगे। जब तक यह नहीं होता, तब तक आईटी ऐक्ट-67 का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि संवेदनशील इलाकों में भड़काऊ वीडियो प्रसारित नहीं हो पाएं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर भी यह दबाव बनाया जा सकता है कि फर्जी वीडियो या खबरों की जानकारी मिलते ही वे तुरंत उसे डिलीट करें। फिलहाल अदालती आदेश द्वारा ही ऐसा करना मुमकिन है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया होती है। फर्जी खबरों का नुकसान तुरंत होता है, इसलिए इसे रोकने के उपाय भी जल्द अमल में लाए जाने चाहिए। नया कानून जब बनेगा तब बनेगा, फिलहाल तो मौजूदा कानूनी प्रावधानों का ही सकारात्मक इस्तेमाल जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सत्य पर दृढ़ रहने वाले युवा ही भारत का भविष्य

वीर हृदय युवकों, परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना मृत्यु है। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो, तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और अदम्य साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों से मैं पना मूलमंत्र घोषित करता आया हूं-प्रयत्न करते रहो। मैं अब भी कहता हूं कि अकिंचन प्रयत्न करते चलो। धीरज धरो, न धन से काम होता है, न यश काम आता है, न विद्या। प्रेम से ही सबकुछ होता है। स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी र उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला है। दूसरों को हानि न पहुंचाते हे। मनुष्य को विचार और उसे व्यक्त करने की स्वंतत्रता मिलनी चाहिए। उसे खान-पान, पोशाक, पहनावा, विवाह-शादी हर बात क में स्वाधीनता मिलनी चाहे। भारत को उटना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, स्वहित की बुराइयों को ऐसा धक्का देना होगा कि वह टकराती हुई अटलांटिक महासागर में जा गिरे। प्राचीन धर्म में बुराइयों को हटा दो, तभी तुम्हें संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल पाएगा। मुझे विश्वास है कि यह संभव है और एक दिन ऐसा जरूर होगा। एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो, जहां सद्विचार वाले लोग रहें, फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। साहसी बच्चों, आगे बढ़ों। तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। सर्तक रहो, जो कुछ असत्य है, उसे पास न फटकने दो। सत्य पर दृढ़ रहो तभी सफल होंगे। भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है। काम करते रहो। मैं चाहता हूं कि हममें किसी प्रकार की कपटता, दुष्टता न रहें।

न्यूज ब्रीफ

वाहन दुर्घटना में दो की मौत

माही की गूंज, पेटलावद/बामनिया।

सड़क हादसों में आए दिन हो रही मौतों का आंकड़ा लगातार बढता जा रहा है। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे यातायात नियमों के जागरूता अभियान का भी वाहन चालकों पर असर नहीं देखा जा रहा है। बिना हेलमेट के वाहन चालक अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं । यहां रविवार को लगभग 8 बजे बामनिया से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम रामपुरिया में दो मोटर साइकिल के आपस में टकराने से बामनिया के एक युवक सहित एक अन्य की मौत हो गई। चौकी बामनिया से मिली जानकारी के अनुसार बामनिया निवासी लतीफपिता सफी बामनिया से पेटलावद के लिए जाते समय समाने से आ रही दुपहिया वाहन जिसको प्रताप पिता बापू डामर निवासी झौंसर चला था। दोनों वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन चालकों की मौके पर मौत हो गई थी। दोनों को पेटलावद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पेटलावद पहुंचाया गया। जहां दोनो की मौत की पुष्टि हो गई । प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों को सिर में गंभीर चोट लगी। जिससे दोनों की मौत हो गई यदि हेलमेट होता तो शायद जान बच जाती। पुलिस चौकी बामनिया ने मामला दर्ज कर लिया है।

बामनिया से रायपुरिया के मध्य में पूरे रास्ते में मुख्यमार्ग से अंदर बसे गांवों में आवजाही के लिए पक्की सड़कें बनी हुई। जिन पर मुख्य मार्ग से सड़क जुड़ने से पूर्व किसी प्रकार के गति अवरोधक बने हुए नहीं है। जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता हैं। वाहन चालक कई बार तेज गति से मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं। जिससे मुख्य रोड से गुजर रहे वाहनों की चपटे में आ जाते हैं या वाहनो को अपनी चपेट में ले लेते हैं। रायपुरिया से पेटलावद के पन्द्रह किलोमीटर की दूरी में लगभग चार-पांच गिट्टी प्लांट लगे हैं। जहां से अक्सर डम्फर और ट्रेक्टर अंध गति से मुख्य मार्ग से गिट्टी प्लांट पर आवा-जाही करते है। साथ ही रोड पर गिट्टी तक बिखेर देते हैं, जो रोज सडक दुर्घटना को खुला आमंत्रण देती हैं। जिला जनपद सदस्य कलावती गेहलोत ने मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़को पर गति अवरोधक बनाकर वाहन की स्पीड नियंत्रण हेतु बोर्ड लगाने की मांग की है।

उपाध्याय हुये सम्मानित

माही की गूंज, झाबुआ। श्री काव्य सागर साहित्यिक संस्था इन्दौर व्दारा साहित्य के प्रचार-प्रसार एवं उत्थान के लिए झाबुआ के वरिष्ठ साहित्यकार पं. गणेश उपाध्याय का सम्मान राष्ट्रीय कवि पं. सत्यनारायण सत्तन तथा पं.योगेन्द्र जी महंत के व्दारा किया गया। कवि गुरु सत्तन ने मोतियों की माला पहनाकर शाल श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र प्रदान किया।

धड़ल्ले से हो रही जंगलो की कटाई, वन विभाग का नही है इस ओर ध्यान

वन्य प्राणियों के लिए 2014 के बाद अभी तक नही हुआ जिले में सर्वे

माही की गूंज, झाबुआ।

ये हालात है जंगलो की।

अव्यवस्थाओ का अंबार है रोपणी में।

खाली पडे रहते है कार्यालय।

जिले का वन विभाग केवल कागजी खाना पूर्ति तक सीमित हो गया है, यह कहा जावे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि एसी कमरों में टेबल कुर्सियों पर बैठ कर यहां प्रगति पर प्रगति दर्शाने में विभाग पीछे नहीं रहता है किन्तु विभाग के पास 2014 के बाद से जमीनी धरातल पर कितना काम किया गया तथा प्रतिवर्ष पौधारोपण के नाम पर लाखों, करोड़ो खर्च होने के बाद भी जिले के तीनों रेंजो झाबुआ, थांदला एवं पेटलावद में वनों का रकबा बढ़ने की बजाय घटता ही जा रहा है। अनाप शनाप वृक्षों की कटाई माफियाओ के द्वारा की जाकर इस जिले को कभी वनो से आच्छादित माना जाता है, उसकी हालत अब रेगिस्तानी माहौल का ही आभास देने लगी है। अविभाजित झाबुआ जिले के समय आलीराजपुर के शामील रहने के समय जो झाबुआ जिला हरियाली से लबरेज माना जाता रहा है, आलीराजपुर के पृथक जिले के रूप में बन जाने के बाद वनों का अधिकांश क्षेत्र आलीराजपुर में चला गया है।

प्रदेश एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वनों के सरंक्षण के साथ वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये काफी धनराशि भी इस आदिवासी अंचल में खर्च की गई है, यदि इतनी राशि किसानों को अपने खेतों की मेडो, के साथ ही वृक्षारोपण आदि के लिये दे दी जाती तो पिछले 10 बरसों में यह अंचल हरियाली से आच्छादित हो सकता था। किन्तु सरकारी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही उनके कथिम मूल्यांकन के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, यह सामने दिखाई दे रहा है। झाबुआ नगर की हाथीपावा पहाडी को वन विभाग एक आदर्श के रूप में सबको बताती रहती है किन्तु वास्तव में देखा जावे तो हाथीपावा का कायाकल्प तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महेशचन्द्र जैन एवं कलेक्टर आशीष सक्सैना के अलावा,शिवगंगा के हलमा अभियान को ही जाता है। जिसके चलते पूरे जिले में सिर्फ यही पहाड़ी आयडियल बन पाई है, इसमें जनसहयोग को भी नकारा नही जासकता है।

लंबे समय से नही किया विभाग ने सर्वे

वन विभाग द्वारा 2014 के बाद से जिले में किसी भी प्रकार का सर्वे या भौतिक सत्यापन मूल्यांकन नही किया जाना भी विभाग की कार्यप्रणाली को सवालिया निशान के घेरे में खडा करता है। विभाग द्वारा शासन की योजनाओं के तहत अभी तक व्यक्तिगत तौर पर 1485 पट्टे अभी तक आवंटित किए गए हैं 1438 वितरित किए जा चुके हैं,तथा बकौल विभागीय सूत्रों के 47 शेष बचे हैं है जिन्हे स्वीकृत किया जाचुका है इस तरह कुल 1450 पट्टे व्यक्तिगत तौर पर आवंटित हुए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार नियमों के अनुसार 4 हेक्टेयर से ज्यादा किसी भी परिवार भी नहीं दे सकते हैं। वन विभाग का कहना है कि वितरित किये गये पट्टो का परिक्षण एमपी वन मित्र के पोर्टल के अन्तर्गत किया गया था जिसके तहत पूर्व के 2720 वन भूमि के पट्टे निरस्त किये गये है।

प्रकरणों का नहीं हो पा रहा निपटारा

जिले के वन विभाग का रकबा वन विभाग के अनुसार 73474 हेक्टेयर में फैला हुआ है जो जिले के क्षेत्रफल का 21.24 प्रतिशत है। जिले में तीन रेज पेटलावद, थांदला एवं झाबुआ में बटा हुआ है। वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक विभिन्न मामलों के 118 प्रकरणो में 78.028 हेक्टेयर के मामलें विचाराधीन होकर कोर्ट में चल रहें है। थांदला रेंज में 12 प्रकरण 5.750 हेक्टेयर के तथा झाबुआ रेंज में 46.318 हेक्टेयर वन भूमि के 66 प्रकरण, एवं पेटलावद में 25.958 हेक्टेयर वन भूमिक के 40 प्रकरण 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2019 तक चल रहें है। वन विभाग के अनुसार ही दिये गये आंकडो के अनुसार जिले में जंगलों की अवैध कटाई के 95 प्रकरण बनाये गये थे जिसमें 31 प्रकरण अवैध कटाई के होकर 81 प्रकरणों का निराकरण किया जाचुका है तथा शेष प्रकरण न्यायालय मे प्रकियाधीन एवं विचाराधीन है।

वन्य पशुओ की संख्या भी दर्शाई पुरानी

जिले में जंगलों की कटाई के साथ ही वन्य पशुओं की संख्या में भी कमी परिलक्षित हुई है। विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार वन्य प्राणी गुजरात एवं राजस्थान की सीमा से जिले की सीमायें लगी होने के कारण वे यहां आ जाते है लेकिन कुछ ही समय में रास्ता मिलते ही वे वापस चले जाते है। वन विभाग के अनुसार वन्य प्राणियों को रेस्क्यू करने के लिये वन विभाग द्वारा सूचना मिलने पर आवश्यकतानुसार रेस्क्यू टीमों का गठन करके यथा समय उन्हे पकडने की कार्यवाही भी करती है। किन्तु झाबुआ जिले के संदर्भ में देखे तो यहां इस प्रकार की कोई टीम का अस्तित्व ही नही है तथा सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही यह कार्य किया जाता है।

पुराने आंकड़े पर ही चल रहा कार्य

वन विभाग की लापरवाही एवं ढुलमुल कार्यप्रणाली का यह आलम है कि माह फरवरी 2014 की स्थिति में ही आंकड़े उपलब्ध है। इसके बाद न तो भ्रमण किया गया ना ही भौतिक सत्यापन की दिशा में कोई काम हुआ है। वर्ष 2014 की स्थिति में जिले में वन्यप्राणियों की संख्या में नीलगाय 227, सियार 121, खरगोश 108, लोमड़ी 51, लकड़बग्घा 35, जंगलीकुत्ता 5, जंगलीसूअर 16, लंगूर 376, लालमुंह का बंदर 73, मोर 10830, भेड़िया 25, इस तरह जिले में सभी प्रकार के वन्यप्राणियों कुल संख्या 11867 हैं। सबसे चौकाने वाली तो यह है कि 2014 में 24 दिन के भ्रमण के अंदर इस प्रकार की इन्हें जानकारी प्राप्त हुई है। उसके बाद में आज तक इनके पास वन्य प्राणियों की ताजा स्थिति में जानकारी नहीं है। इस जानकारी के अंदर तेंदुआ झाबुआ जिले में कहीं से कहीं तक नहीं बताये गये है।

जाहिर है जिले में तीन रेंज मे विभक्त जिले का वन विभाग आज भी वनों, के अलावा सडकों के किनारे भी बरसों पूराने वृक्षों की होने वाली कटाई को रोकपाने में अक्षम साबित हो रहा है। जिस विभाग को जिले में पर्यावरण सरंक्षण को देखते हुए वनों को बढाने का काम करना चाहिए, वह केवल कागजी खाना पूर्ति के अलावा कुछ कर रहा हो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगता है। ऐसे में झाबुआ जो आज से 5 दशक पूर्व जिस तरह हरियाली से आच्छादित दिखाई देता था, वही जिला आज सूखे जंगलों, ठूंठो, विरान पहाडियों के रूप में दिखाई दे रहा है। यदि समय रहते कदम नही उठाये गये तो तय है कि राजस्थान के रेगिस्तान का प्रभाव इस सीमावर्ती जिले को भी प्रभावित करेगा।

त्यौहारों की आमद के साथ ही घर-घर बधाई देने पहूंच रहे किन्नर

किन्नरों का पौराणिक काल से रहा है महत्व, इनके आशीर्वाद मंगलकारी होते है- डा. त्रिवेदी

माही की गूंज, झाबुआ। इन दिनों होलिकोत्सव पर्व की आमद के पूर्व ही नगर सहित अंचल में किन्नर लोगों द्वारा गली, मोहल्लो में घर-घर जाकर ढोलक, हार्मोनियम, मंजीरों की संगीतमय स्वर लहरियों के बीच बधाईयां देते नजर आ रहे है। तथा हर घर जाकर नेक के नाम पर धनराशि एकत्रित करते देखे जा सकते है। नगर में होलिकोत्सव की बधाई देने के लिए किन्नर समाज की मुखिया रानीबेन के नेतृत्व में रमीमा, रीटा, आंनदी, शानु, बुलबुल आदि किन्नर नगर के सभी बाजारों तथा मोहल्लों में घूमकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे है। किन्नर समाज के बारे में कहा जाता है कि इन्हे हर मांगलिक अवसर हो या धार्मिक कार्यक्रम, इनकी उपस्थिति को मंगलकारी माना जाता है। इतिहासविद् डा. केके त्रिवेदी का कहना है कि किन्नरों का वर्णन पुराणों में भी उल्लेखित है, किन्नर समाज का पौराणिक महत्व भी है। जब भी भगवान अवतार लेते है तब किन्नर, देवता, नाग सभी जातियों ने वहां पहूंच कर भगवान का दर्शन किया। उस दृष्टि से किन्नर प्रजाति पौराणिक कालीन है और उनकी उपस्थिति किसी भी समारोह के लिए मंगलकारी होती है। और यही भारत की सनातन परंम्परा आज तक भारत में विद्यमान है। समाज के लोग जिन लोगों को थर्ड जेंडर अर्थात किन्नर कहा जाता है, उनके प्रति सदभाव रखते है तथा जब कभी भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो वे चाहते है कि वे वहां उपस्थित रहें और उनका आशीर्वाद मिले। शादी के समय में और जब बच्चे का नाम करण होता है या जन्म होता है तब किन्नरों की उपस्थिति घर के अंदर प्रवेश शुभ माना जाता है। किन्नर के प्रति शासन का रवैया भी सकारात्मक होकर एक अच्छे नागरिक की तरह इन्हे मान्यता दी गई है। पहले पुरूष एवं महिला लिंग माना जाता रहा है किन्तु अब इन्हे थर्ड जेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । किन्नर प्रजाति समाज के प्रति उनका निर्माण प्रकृर्ति प्रदत्त है। पर वर्तमान समाज ने भी उन्हे सम्मान देना शुरू कर दिया है प्राचिन काल में तो उन्हे सम्मान मिलता ही रहा है। प्रकृति ने मानव जाति में नर-नारी के बिना एक अन्य वर्ग की भी सृष्टि की है, जो न तो पूरी तरह नर होता है या नारी जिन्हें लोग किन्नर या फिर ट्रासजेंडर के नाम से संबोधित करते हैं। इन्हें पुराणों में शिखंडी, बृहन्नला, किन्नर आदि नामों से संबोधित किया गया हैं। किन्नर मुखिया रानी बहिन का कहना भी है कि जाति-पाति, ऊंच-नीच के भेद भाव से परे हट कर साम्प्रदायिक सौहार्द्रता को कायम करना ही किन्नर वर्ग का लक्ष्य रहता है। हिन्दु, मुस्लिम सहित सभी वार त्यौहारों को पूरी श्रद्धा के साथ हम लोग मनाते है और समाज में शांति एवं अमन के साथ ही भाईचारे का संदेश देना भी हमारा मुख्य लक्ष्य होता है।

सांसद ने पट्टा देने के लिए लिखा पत्र

राधाकिशन गुर्जर को पट्टा देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी को लिखे सासंद गुमानसिंह का पत्र।

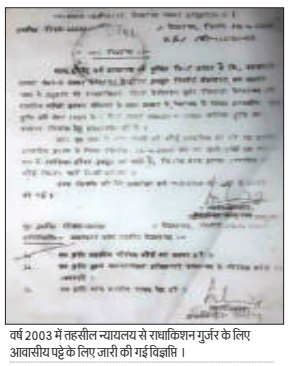
वर्ष 2003 में तहसील न्यायलय से राधाकिशन गुर्जर के लिए आवासीय पट्टे के लिए जारी की गई विज्ञप्ति ।

माही की गूंज, पेटलावद। नगर में अतिक्रमण मुहिम के दौरान दो बार की बर्बर कार्यवाही में अतिक्रमण के नाम हटाए गए पेटलावद निवासी राधाकिशन पिता देवीलाल गुर्जर को राजीव गांधी आश्रय योजना में तहत पट्टा देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद को पत्र लिखा हैं। जिसमें सांसद गुमानसिंह डामर ने मामले में आवश्क कार्यवाही कर अवगत कराने की बात प्रशासन से की है। अतिक्रमण की भेंट चढा राधाकिशन का परिवार बेघर हो चुका है और अतिक्रमण के नाम पर राजस्व अमले ने पहने दुकान और फिर कुछ दिनों के बाद मकान तक तोडकर परिवार को सडक पर फेंक दिया था। राधाकिशन के पास दस्तावेज तक देखने को प्रशासन तैयार नहीं था। ऐसे में पीडित परिवार ने सांसद प्रतिनिधि राजेश कांसवा के माध्यम से सांसद गुमानसिंह डामर से गुहार लगाई थी। मामले में सांसद प्रतिनिधि राजेश कांसवा ने बताया कि सांसद डामर द्वारा भेजे गये पत्र को लेकर अनुविभागीय अधिकारी एमएल मालवीय से मिला हूं और अधिकारी द्वारा मामले में हर संभव मदद करने की बात कही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2003 में भी अतिक्रमण मुहिम के दौरान के राधाकिशन गुर्जर को हटाया गया था जिसको लेकर राधाकिशन का परिवार न्यायालय में गया था। जहां तत्कालिक अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त सर्वे नंबर 1105 की भूमि पर दिनांक 10.04.2003 को एक विज्ञप्ति जारी कि थी। जिसमें पेटलावद कस्बा क्षेत्र में स्थित शासकीय नजुल के सर्वे नंबर 1105 पर एक हजार स्वेक्यर फीट का पट्टा उक्त परिवार को राजीव गांधी आश्रय योजना में दिए जाने की बात है। जिस पर किसी के द्वारा आपत्ति दर्ज नही कराई गई, लेकिन नगर परिषद् में किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं होने के अभाव में उक्त भूमि नगर परिषद् में नामान्तरण नहीं की जा सकी थी और उसी को आधार मानकर राजस्व और नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटाया था। सांसद के पत्र के बाद परिवार को अपनी भूमि मिलने की आश लगी है। वही परिवार मामले को लेकर एक बार फिर न्यायालय की शरण में जानें की बात कर रहा है। पीडित राधाकिशन की पत्नि बंसतीबाई गुर्जर ने बताया कि मेरे द्वारा मामले कई बार अनुविभागीय अधिकारी से मिलना चाहा, लेकिन मेरा आवेदन तक नहीं लिया गया। मेरे पति राधाकिशन गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और हमारे परिवार के भूखे मरने की स्थिति बन गई है।

बाबा देव दर्शन कर लौट रहे लोगों को बस ने मारी टक्कर

माही की गूंज, कुंदनपुर। समोई बाबा देव से दर्शनार्थियों के वाहन को सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। घटना शुक्रवार शाम 6 बजे कुन्दनपुर के पास काल्याकोतेडी की है। टक्कर इतनी भीषण थी कि तूफान वाहन चकनाचूर हो गई और अन्दर बैठी सवारियां खिड़की दरवाजे तोड़कर बाहर आ गिरी। घटना में तूफान वाहन में सवार 5 लोग घायल हुए है। घायलों को रानापुर अस्पताल भेजा गया। झाबुआ जिले के थांदला तहसील थाना क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपाड़ा से कुछ लोग तूफान वाहन क्रमांक एमपी 45 बीबी 2444 में सवार होकर समोई बाबा देव दर्शन कर स्थित वापस गांव लौट रहे थे। शुक्रवार शाम 6 बजे कुन्दनपुर से कुछ दूर काल्याकोतेडी पर कुन्दनपुर से रानापुर की ओर जा मालधारी ट्रेवल्स की बस क्रमांक एमपी 09 एफए 2802 तेज गति से टक्कर मार दी। बस की टक्कर से तुफान वाहन बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कुन्दनपुर पुलिस 108 वाहन व पुलिस बल मौके पर पहुंचा। यहां से घायलों को रानापुर अस्पताल पहुंचाया गया।

आखिर हटाए गए थाना प्रभारी दिनेश शर्मा

नए थाना प्रभारी पर होगी अपराध नियंत्रण की चुनौती

माही की गूंज, पेटलावद। लगातार अपनी विवादित छवि से सुर्खियों में रहने वाले थाना प्रभारी दिनेश शर्मा को थाना पेटलावद से हटाकर महिला प्रकोष्ठ थाना झाबुआ भेज दिया गया। दिनेश शर्मा के हटाये जाने से नगर में मिली जुली प्रक्रिया सामने आ रही है। कई लोगों का मानना है कि भू-माफिया ने जयस के कंधे पर बदूंक रखकर सरकार पर दबाब बनवाकर थाना प्रभारी को हटावाया है, तो कई लोगो का मानना है कि थाना प्रभारी के विवादित व्यवहार के कारण रवानगी हुई है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी दिनेश शर्मा के पदस्थ होने के बाद लगातार शिकायतें विभाग, मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक हो रही थी। वहीं नगर में एक के बाद एक हो रही चोरी की घटना में पुलिस को थाना प्रभारी के नेतृत्व में कोई बड़ी सफलता नही मिल सकी है। जिसके चलते थाना प्रभारी को विभागीय कार्यवाही के तहत फेरबदल के रूप में थाना पेटलावद से हटाया गया हैं। साहब रवानगी के बाद सोशल मीडिया पर थाना प्रभारी के समर्थन में की गई पोस्ट पर सट्टे के व्यापार से जुडे कुछ नामचीन भी साहब के समर्थन मे कमेंट करते नजर आए। यातायात व्यवस्था में सराहनीय कार्य कर नगर की चरमाराई यातायात व्यववस्था में अच्छा खासे सुधार के कारण नगर के आमजन को दिनेश शर्मा की कमी जरूर खलेगी।

नए थाना प्रभारी भी एक्शन में

नए थाना प्रभारी संजय रावत ने आते ही नगर की यातायात व्यवस्था के साथ-साथ नगर के ढाबों पर अवैध रूप से बिक रही शराब को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। थाना प्रभारी संजय रावत का कहना है कि अपराध नियत्रंण कर अपराधियों और अवैध कारोबारियों पर कडी कार्यवाही करने पर विशेष ध्यान रहेगा। अब देखना होगा कि नए थाना प्रभारी कितना खरे उतरते है। पिछले दिनों जैन कॉलोनी मे हुई बड़ी चोरी की साथ-साथ नगर की के स्थानों पर दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात और वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी जो कि पुलिस की पकड से अब तक दूर है। उनको पकडना नए थाना प्रभारी के लिए बडी चुनौती रहेगी।

भगोरिया पर्व की जोर-शोर से तैयारियां, आज मनेगा भगोरिया

माही की गूंज, सारंगी। आदिवासी समाज का प्रसिद्ध भगोरिया पर्व झाबुआ जिले के थांदला हॉट से शुरू हो गया है। आज गुरुवार को सारंगी में भगोरिया पर्व मनाया जाएगा। इस भगोरिया हाट में आदिवासी समाज बड़ी संख्या में सज धज कर बाजार में आएंगे और मस्ती में मस्त होकर मादल की थाप और थाली की झंकार खूब झूमेंगे। ग्रामीण युवक-युवतियां आदिवासी समाज इस भगोरिया हाट के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के त्योहार हो या शादी ब्याह अपनी अलग ही रंग बिखेरते हैं।

सारंगी में भी भगोरिया हाट को लेकर व्यापारियों ने जोर-शोर से तैयारियां कर रखी है। इस पर्व को मनाने के साथ ही ग्रामीणों की खुशियों का रंग भी अलग होता है और उसी हर्ष उल्लास उत्साह से ग्रामीण भगोरिया हाट मनाते हैं वर्षो से चली आ रही इस भगोरिया हाट की परंपरा में समय के साथ जरूर परिवर्तन हुआ लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ है। अलग-अलग झुंड बनाकर ग्रामीण मांदल की थाप पर नृत्य करेंगे। अल सुबह से भगोरिया हाट में ग्रामीणों का बाजार में आना प्रारंभ हो जाता है एक समान कपड़े पहन कर ग्रामीण की युवक- युवतियां आती है और भगोरिया हाट में लगने वाले झूलो के साथ खाने पीने की चीजों का भी आनंद उठाते हैं साथी अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र से आती है और सब अपने अपने गांव की मा दलों पर थिरकते है बस स्टैंड पर सभी ढोल मादल लेकर इकट्ठे होते हैं और भगोरिया पर्व का आनंद लेते हैं इसमें कॉन्ग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टी के नेता भी ग्रामीणों के साथ मिलकर भगोरिया पर्व की बधाई देते हैं , पूर्व जनपद पेटलावद के अध्यक्ष हीरालाल डाबी ने भगोरिया पर्व को लेकर बताया कि यह भगोरिया पर्व हमारे पूर्वजों के समय से मनाया जा रहा है इस दिन का इंतजार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पूरे 1 वर्ष इंतजार रहता है इस वर्ष भी भगोरिया हाट बड़े उत्साह उमंग साथ मनाया जाएगा डाबी ने बताया कि क्षेत्र आदिवासी होने के कारण यहां भगोरिया हाट का काफी उत्साह है इस भगोरिया पर्व को कॉफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

चित्तौडी रूंडी के बाशिंदे पानी के लिए परेशान, हर गर्मी में झेलते है जल संकट, ग्राम पंचायत नहीं ले रही सुध

माही की गूंज, बामनिया। गौरव भंडारी

बामनिया पंचायत के मुख्य गांव से लगे चित्तौडी रूंडी फलिये के रहवासी पिछले कई वर्षो से पेयजल की समस्या से जुझ रहे है। कहने को ग्राम पंचायत को सरकार ने दो करोड़ की नलजल योजना दी है, लेकिन दो करोड़ की नल-जल योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत की पांच हजार की आबादी तक भी पंचायत पानी पहुंचाने में सफल नहीं हो सकी है। बामनिया से लगे फलिये चित्तौडी रूंडी में पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से गरीब परिवारों को निजी टैंकरों से या फिर एक किलोमीटर दूर से जाकर पीने के पानी के व्यवस्था करनी पड़ रही है। फलिये में लगे तीनों हैंडपंप गर्मी से पूर्व ही बंद हो गए है। जबकि एक हैंडपम्प में ग्राम पंचायत ने मोटर डालने का प्रयास भी किया, लेकिन मोटर हॉल में ही फंस गई। जिसे आज तक ग्राम पंचायत वापस निकलवाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया। पिछली गर्मी में मचे पानी के हाहाकार के बीच ग्राम पंचायत ने एक पानी की टंकी फलिये में रखी थी, लेकिन उसमें पानी पहुंचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। फलिये के नागरिक यंशवत डामर ने बताया कि हम लोग पिछले कई वर्षो से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। पिछली पंचायत के प्रयासों से दो करोड की नल-जल योजना स्वीकृत हुई तो हमका उम्मीद थी की हमारी समस्या का स्थाई हल निकल जाएगा लेकिन वर्तमान पंचायत द्वारा हामरे फलिये तक डाली गई पाईप लाइन में तीन साल बाद भी पानी नही आ सका है। ग्राम पंचायत के चित्तौडी रूंडी फलिये से पंच गुमानसिंह ने बताया कि मेरे द्वारा हर बार ग्राम पंचायत को पानी की व्यवस्था के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नही की जाती है। हर बार गर्मी में पानी की समस्या से जुझना पडता है।

पांच टैंकर पानी के चारो गायब

विकासखण्ड की बडी पंचायत में से एक बामनिया पंचायत में होने वाली पानी की समस्या से निपटने के लिए ग्राम पंचायत को अलग-अलग मद से चार पानी के टेंकर उपलब्ध कराये थे। जिसमें दो पूर्व राज्य सभा सांसद अनिल माधव दवे , एक पूर्व विधायक निर्मला भूरिया द्वारा विधायक निधि, जिला पंचायत सदस्य की ओर दिया गया था। जबकि एक टेंकर ग्राम पंचायत का खुद का था। वर्तमान में चारों टेंकर ग्राम पंचायत के पास नहीं दिख रहे है। मामले में पूर्व उपसरंपच अजय जैन ने बताया कि हमारे कार्यकाल समाप्त होने के बाद नवीन पंचायत को समस्त साधन टैंकर-ट्रेक्टर आदि सुपुर्द किये थे जो कि वर्तमान में सभी गायब है जो कि जांच का विषय है। ग्राम पंचायत को आम जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। नल-जल योजना के माध्यम से चित्तौडीरूडी में घर-घर कनेक्शन देना था जो कि वर्तमान पंचायत ने दिखावे की लाइन एक स्थान पर लाकर छोड दी। जिसमें तीन साल बाद भी पानी नही पहुंच सका है।

एसडीएम ने किसानों की समस्याएं सुनी, व्यापारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश

माही की गूंज, झाबुआ। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व झाबुआ अभयसिह खराडी ने मंगलवार को यहां कलेक्ट्रेट में किसानों की समस्याए सुनी। किसानो ने अवगत कराया कि बाबेल कम्पाउण्ड झाबुआ व्यापारी अजीत पुरोहित पिता मोहलाल पुरोहित तथा अजय पिता मोहनलाल पुरोहित द्वारा पार्श्वनार्थ जैन मंदिर मण्डी के सामने रास्ते पर दुकान लगाकर 16 फरवरी को स्थानीय हाट बाजार के समय किसानो से कच्ची रस्सीदे के माध्यम से किसानो से कपास की खरीदी की गई। जिसकी सम्पूर्ण राशि का भुगतान न अभी तक नहीं किया गया है। किसानो ने उक्त भुगतान संबंधित व्यापारी से षीघ्र दिलवाये जाने का अनुरोध किया।

एसडीएम खराडी ने कलेक्टर प्रबल सिपाहा के निर्देशानुसार इन व्यापारियों द्वारा मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 37 (2) का उल्लंघन एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 का उल्लंघन करने पर इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए। खराडी ने मण्डी संचिव को मेसर्स राजट्रेडर्स अजीत पुरोहित की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए है ।

एमपी ऑनलाइन द्वारा किसानों के लिए शुरू हुई प्रमाणित खसरा नकल की शुरुआत

माही की गूंज, सनावद। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रमाणित खसरा नकल लेने के लिए एक सेंटर की शुरुआत की है। जिसके तहत अब किसान आम नागरिक यह सुविधा के लिए भू अभिलेख विभाग और एमपी ऑनलाइन द्वारा मंजुश्री फोटो कॉपी सेंटर पर नवीन सुविधा केंद्र शुरू हुआ। नागरिक एमपी ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से आवेदन देकर डिजिटल हस्ताक्षर युक्त खसरा नकल बी1 नकल एवं नक्शा 30 मिनट में प्राप्त कर सकेंगे। इस सुविधा का शुभारंभ सोमवार को नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल पटवारी नारायण दस्साने केंद्र संचालक सुमित सोनी द्वारा किया गया। इस दौरान कृषकों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त नकल का वितरण किया। संचालक सोनी ने बताया कि 30 रुपये की फीस जमा करवाकर नागरिक सेंटर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं किसानों ने बताया कि अब खसरा नकल नक्शा और बी1 के लिए एक जगह आवेदन कर प्राप्त हो सकेगी।

चने की फसल लेकर आए किसानों से पटा मंडी परिसर

मंडी खुलते ही नीलामी के पूर्व ही कम भाव मिलने से नाराज किसानों ने हंगामा कर दिया

माही की गूंज, सनावद।

नगर की कृषि उपज मंडी में सोमवार को मंडी खुलते ही बड़ी संख्या में चने की उपज लेकर आने वाले किसानों से मंडी पट गई। 1 दिन पूर्व से किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। जो सोमवार सुबह तक चलता रहा। जिसके बाद मंडी खुलते ही नीलामी के पूर्व ही कम भाव मिलने से नाराज किसानों ने हंगामा कर दिया। जिसके बाद मंडी सेक्रेटरी ने किसानों से सामंजस्य बनाकर नीलामी शुरू करवाई। लेकिन फिर भी भावों में बढ़ोतरी नहीं होने पर किसानों ने नीलामी रुकवा दी। और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की बात कही। इसके बाद नायब तहसीलदार एवं भारसाधक अधिकारी सुखदेव डाबर ने कृषक एवं व्यापारीयो से अलग अलग चर्चा कर करीब 2 बजे पुनः नीलामी शुरू करवाई। किसानों का आरोप था कि मंडी अन्य मंडी से कम भाव मिल रहा है। उसमें 5 से 7 का अंतर आ रहा है। जो किसान के लिए दुखदाई है। इसी बात से नाराज करीब 200 किसानों ने मंडी में हंगामा किया। नायब तहसीलदार डाबर के हस्तक्षेप के बाद नीलामी शुरू हुई। जिसके बाद 51 सौ 53 सौ एवं अन्य भाव में चने की खरीदी की गई।

पूर्व में भी बन चुकी है यह स्थिति

किसानों ने बताया कि चने के वाहनों की बम्परआवक के कारण यह स्थिति बनी। पूर्व में भी यह स्थिति बन चुकी है। जबकि यहां चने की उपज का 57 सौ तक भाव दिया गया है। कम गाड़ी की आवक पर व्यापारी अच्छे काम देते हैं। जबकि अधिक वाहन आ जाने से व्यापारी खरीदी में आनाकानी करते हैं। किसान सुनील पटेल रावेर खेड़ी दिनेश बिर्ला तमोलिया अनिल पटेल बड़गांव अनिल बिर्ला रावेर खेड़ी रविंद्र पटेल ढसगांव मनोज पटेल बड़गांव चंदू बिर्ला तमोलिया शांतिलाल नांदिया टोकसर कड़वा जी पटेल ढक लगांव दिनेश डीके बड़गांव भरत पटेल सांगी ने आरोप लगाया कि मंडी के कुछ कर्मचारी व्यापारियों के साथ मिलकर किसानों की बात को दबाने की कोशिश करते हैं। जबकि विरोध के दौरान कुछ व्यापारियों ने किसानों से यहां से माल वापस ले जाने की बात भी कही। किसानों ने कहाँ कि जब किसान मंडी में अपनी उपज लेकर नहीं आएंगे तो मंडी का क्या उचित है। मंडी को ताला लगाने के प्रयास स्थानीय कर्मचारी कर रहे हैं। किसानों इस घटनाक्रम की जानकारी कृषिमंत्री सचिन यादव से करने की बात कही है।

किसानों का समस्याओं के समाधान के लिए किसान मंडी व्यापारी सहित अधिकारियों से चर्चा की गई। वहीं उपज के अनुसार किसानों की फसल खरीदी की गई। तीन बार नीलामी रुकी। लेकिन आखिर में किसानों ने अपनी उपज बेचकर संतुष्टि जाहिर की। कुछ किसान अधिक राशि देने की बात कर रहे थे। जबकि व्यापारी चने की उपज के अनुसार ही खरीदी कर रहे थे। शाम तक सभी किसानों की उपज बेची गई। 51 सौ से नीलामी शुरू हुई। क्वालिटी के अनुसार भाव मिले।

लायनेस क्लब स्नेह के पदरोहन समारोह संपन्न

माही की गूंज, सनावद। लायनेस क्लब द्वारा नगर एवं आसपास के ग्राम के नागरिकों के लिए जो सेवा के प्रयास किए जा रहे हैं। वह काबिले तारीफ है। सदस्य यह गति आगे भी बनाए रखें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत को पूरा कर क्लब के उद्देश्य को सार्थक करें। साथ ही अन्य जिले के अन्य क्षेत्रों में भी लायनेस क्लब स्नेह की गतिविधियां बढ़ाकर और लोगों को इस में जोड़े। यह बात पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने लायनेस क्लब स्नेह के पदरोहन समारोह के दौरान व्यक्त किए। श्री यादव ने सदस्यों से कहा कि सनावद बड़वाह इंदौर खंडवा सहित अन्य स्थानों पर क्लब सेवा सप्ताह के तहत कार्य कर रहा है। इसे जिले के कसरावद खरगोन नगर एवं क्षेत्र में भी जोड़कर इसे धरातल पर मजबूत बनाये। क्लब के गवर्नर अजय सेंगर ने मनोनीत सदस्यों को पिन लगाकर गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही किए जा रहे कार्यों पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि लायनेस क्लब के सेवा कार्यो को सनावद के सदस्य निरंतर बढ़ा रहे हैं। इसमें और नई-नई गतिविधियां जोड़कर जरूरतमंदों के लिए कारगर कदम उठाएं। विधायक सचिन बिर्ला ने कहा कि लायनेस क्लब ही एक ऐसी संस्था है। जिसमें पति पत्नी दोनों सेवा कार्यों में आगे आकर मानवता की सेवा में लगे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद ताराचंद पटेल डिस्ट्रिक प्रेसिडेंट सुनीता फरक्या परविंदर सिंह भाटिया गुरदीप सिंह भाटिया सहित अन्य अतिथि मंचासीन थे। क्लब के अध्यक्ष अनिता भागचंद जैन ने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल की गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही भविष्य के लिए नई कार्ययोजना बनाकर क्लब की गतिविधि बढ़ाने की बात कहते हुए अतिथियों को विश्वास दिलाया। श्रीमती जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि क्लब की सदस्य बहनों द्वारा पिछले 1 साल में 25 से अधिक युवतियों का कन्यादान एक युवती को जंजीरों से मुक्त करवाकर उपचार के लिए इंदौर भेजा। एक युवती को स्वास्थ एवं 1 युवती को रोजगार के लिए आर्थिक मदद की गई। साथ ही क्लब आगे भी ऐसे ही सेवा कार्यों को बढ़-चढ़कर बढ़ाकर इसमें लोगों की सेवा के लिए कार्य करेगा। संचालन शिक्षक राजेन्द्र महावीर सचिव श्वेता पंचोलिया एवं रेणुका गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। आभार भागचंद जैन ने व्यक्त किया। इस दौरान गुडलक डांस ग्रुप के कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तूति दी। आयोजन में लायनेस एवं लायंस क्लब के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

नर्मदा पुल पर ट्रक हुआ दुर्घटना ग्रस्त

माही की गूंज, सनावद। मोरटक्का स्थित नर्मदा पुल पर सोमवार रात 12 बजे एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें शराबी हेल्पर की लापरवाही से ट्रक पुल के रेलिंग तोड़ता हुआ सड़क से नीचे उतर गया। वहीं दुकान के टीन शेड को छतिग्रस्त कर दिया। मां नर्मदा के अंतिम छोर पर ट्रक के हेल्पर की लापरवाही शराब के नशे में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सुबह ट्रक ड्राइवर ट्रक को ढूंढता हुआ उक्त पहुंचा तो हकीकत मालूम हुई। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि सोमवार रात को ट्रक हम हेल्पर के सुपुर्द छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब सुबह बड़वाह में उक्त जगह पर पहुंचे। जहां खड़ा था। तब वाहन नहीं मिला। वही हेल्पर को फोन लगाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफबता रहा था। जब पता लगाते हुए मोरटक्का पुल पर पहुंचे तो ट्रक रेलिंग दौड़ता हुआ पुल के हिस्से से टकराकर क्षतिग्रस्त मिला। चालक ने बताया कि वाहन में काकडे भरे थे। जो नांदेड़ से देवास जा रहे थे। हेल्पर शराब के नशे में था। और ना जाने कब तक वाहन वहां से लेकर चला गया। वह दौड़वा जाने के लिए वाहन लेकर निकला था। लेकिन मोरटक्का पुल पर शराब के नशे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के बाद से हेल्पर की भी तलाश की जा रही है। वहीं दुर्घटना के समय दुकान के बाहर टीनशेड में सो रहे एक बुजुर्ग इस घटना में बाल-बाल बचा। बुजुर्ग हनुमान प्रसाद ने बताया कि मैं सोया हुआ था। दुकान पर लगा एक बांस पैर पर लगा। जब आंख खुली तो देखा ट्रक चालू हालत में सामने खड़ा है। वह तो गनीमत रही की ट्रक का एक पहिया सड़क से नीचे उतर गया था। नहीं तो सीधे मेरे ऊपर आता। यह तो मां नर्मदा की कृपा कृपा थी। कि मुझे कुछ नहीं हुआ।

माता-पिता की स्मृति में एक लाख चौवन हजार राशि धर्म, शिक्षा, गौशाला और समाज को भेंट करने की घोषणा

माही की गूंज, बमनाला। समीपस्थ छोटे से ग्राम शकरखेड़ी के युवा किसान विष्णु राठौड़ ने अपने माता-पिता की स्मृति में धर्म,शिक्षा ,गौशाला और समाज को एक लाख चौवन हजार दो सौ रुपये की राशि भेंट कर एक नई पहल की है। मालूम हो कि राठौड की माताजी कलाबाई (88) पति स्व. शंकरलाल राठौड़ का विगत 21 फरवरी को देहांत हो गया था, जिनके पगड़ी कार्यक्रम में उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित समाजजनों के सामने राठौर समाज की ओम्कारेश्वर में प्रस्तावित नवीन धर्मशाला एवं निर्माणाधीन ओम शांति भवन खरगोन हेतु क्रमशः 51,000-51,000,राठौड समाज बमनाला बाबद बर्तन क्रय एवं प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय,माउंटआबू(राजस्थान) हेतु क्रमशः 21,000-21,000, उभरता राठौर समाज मिशन के प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यक्रम मेरिट में आओ एक लाख रुपये पुरस्कार पाओ एवं गौशाला उपयोग हेतु क्रमशः 5,100-5,100 दान राशि की घोषणा की।उनके द्वारा गौशाला हेतु 21 क्विंटल भूसा भी गौग्रास हेतु भेजा जाएगा। राठौड़ ने बताया कि उनकी स्वर्गीय माताजी अपने अंतिम समय तक स्वस्थ रही ,यदि वे रोगी होती तो अस्पतालों में भारी चिकित्सा खर्च वहन करना स्वाभाविक था। अतः मैं यह मानते हुए उक्त राशि समाजहित में दान कर आत्मशांति का अनुभव कर रहा हूँ। इस अवसर पर राठौड़ युवा प्रकोष्ठ के जिला मार्गदर्शक मोहनलाल राठौर, जिलाध्यक्ष मुकेश राठौर, तहसील संयोजक रविन्द्र राठौर, बमनाला अध्यक्ष श्यामलाल राठौड़, पत्रकार अरुण राठौर, समाजसेवी रमेशचंद्र राठौड, मथुरालाल राठौड, रामलाल राठौड, गजानन्द राठौर, हीरालाल राठौड़, धन्नालाल राठौड़, राधेश्याम राठौड, पंकज राठौड, अनिल राठौड आदि ने श्रद्धासुमन अर्पित कर विष्णु राठौड़ की समाजसेवार्थ दी, सहयोग राशि पर आभार प्रदर्शन किया।

दो सड़क दुर्घटनाओं में 10 घायल

माही की गूंज, सनावद।

सड़क दुर्घटनाओं के बाद नगर के सिविल अस्पताल में 10 घायलों को लाया गया। जिनमें 2 को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया। वहीं अस्पताल में अचानक दुर्घटना के बाद आये घायलो के उपचार के लिए अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। जिसे वहां मौजूद डॉक्टरों ने तत्काल मरीजों का उपचार कर स्थिति को संभाला। सिविल अस्पताल में सोमवार रात 8 बजे क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में 2 सड़क दुर्घटना हुई। जिसमें पहली दुर्घटना बस को अज्ञात बुलेरो वाहन की टक्कर मे बारात से होकर वापस अपने गांव उदयपुर आ जा रहे लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी घटना में एक बच्चे सहित उसकी मां घायल हुए। सड़क दुर्घटना के बाद मोहन सिंह और मुकेश नाम के घायल को इंदौर रैफर किया गया। इस दुर्घटना में 1 साल की बालिका डोली भी घायल हुई। वहीं अस्पताल में मौजूद डॉ एएस चौहान डॉ सुभाष बर्डे डॉ अभिषेक मुकाती एवं स्टाफ ने तत्काल घायलों का उपचार किया।

बगैर बिजली कनेक्शन के आदिवासी परिवारों को मिल रहे हजारों के बिल

माही की गूंज, पंधाना।

सरकारें चाहे जितना आदिवासियों के लिए योजना लाकर लाभ दिलाने का प्रयास कर ले जबाबदार अधिकारी उसे पलिता लगाने मे लगे है। पंधाना ब्लाक के ग्राम बोरखेड़ा के टांडा फाल्या में रह रहे आदिवासी परिवार बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे है।

बोरखेड़ा फाल्या टांडा के आदिवासियों के घरो मे बगैर मिटर कनेक्शन के दो सालो से बिजली बिल मिल रहे है। इनके मकानो मे बिजली विभाग ने मिटर तो लगा दिए है पर उन मिटरों में दो वर्षो से कनेक्शन नहीं किया। जबकि कनेक्शन करना तो दूर बिजली पोल भी गांव में नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ दिवारों पर मिटर लगाकर भुल गए। इस फाल्या टांडा में निवासरत 7 सात आदिवासी परिवार लगातार हजारों के बिल आने से परेशान है। आदिवासी परिवारों ने बिजली विभाग के आधिकारीयों को आपनी समस्या अनेकों बार बताई पर नतीजा सिफर ही रहा। गौरतब है की जब बोरखेड़ा फाल्या टांडा के आदिवासी परिवारों की बगैर कनेक्शन किए हजरो रुपये के बिलो की जानकारी क्षेत्रीय विधायक राम दागोरे को लगी तो उन्होंने पिड़ित आदिवासी परिवरो को भरोसा दिलाया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार की हर समस्याओं को प्राथमिकता से हल करवाउंगा। विधायक राम दागोरे ने जवाबदार बिजली अधिकारियों को समस्या को तत्काल दूर करने के निर्देश देकर मिटर कनेक्शन अविलंब जोड़कर बगैर कनेक्शन लगे बड़े बिलों के भुगतान को माफ करने के भी निर्देश दिए।

हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों ने किया पहला पर्चा हल, परिक्षार्थियों का गुलाब से हुआ स्वागत

माही की गूंज, सनावद।

माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकंडरी कक्षा 12 की परीक्षा सोमवार को हिंदी के पेपर के साथ शुरू हुई। आज कक्षा 10 वी के स

संस्कृत से पहला पेपर आज से शुरू होंगा। इसके लिये नगर के 4 परीक्षा केंद्रों पर करीब 1500 विधार्थी परीक्षा दी। नगर में कन्या शाला बालक उमा एमडी जैन रेवा गुर्जर शिशु मंदिर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमे 2 हजार छात्र छात्राओं ने अपने इस्कूली शिक्षा के अंतिम पायदान को पार करने के लिए प्रयास किया। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारियो के सतत निरक्षण होते रहे।

आसान विशिष्ट हिंदी का पर्चा हल करते हुए खुशी जाहिर की है। छात्रा पूजा इंगला मोहनी तंवर रेणुका नामदेव शोभा बिश्नोई अनिता खेड़े शबनम खान ने बताया कि पहला पेपर हिंदी का जो उम्मदी के अनुसार आसान था। जिसे कम समय मे पूरा किया गया। आगे भी श्रेठ तैयारी कर परीक्षा देंगे। मैं ही कुछ छात्राओं ने बताया कि यह पढ़ाई या परीक्षा ही हमारे आगे के जीवन में नौकरी एवं व्यवसाय के लिए काम आएगी इसके इसलिए इसके लिए विशेष रुप से तैयारी कर रहे हैं

1500 से अधिक बच्चो ने दी परीक्षा-

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस बार नगर में कुछ परीक्षा केंद्रों की कटौती की गई। साथ ही दूसरे परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था को बढ़ाया गया। नगर के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 226 रेवा गुर्जर स्कूल में 219 बालक उच्च तर माध्यमिक विद्यालय में 390 और एमडी जैन में 300 छात्र-छात्राओं ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी।

परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों का गुलाब के फूल, तिलक व मिठाई खिलाकर किया स्वागत

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के जारी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम अनुसार आज दिनांक 02/03/2020 से कक्षा 12 वीं की परीक्षा हिंदी विषय के साथ प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुई। शा उ मा वि अहिरखेड़ा के परीक्षा केंद्र पर प्रातः 8.30 बजे केंद्राध्यक्ष महेश निशोद, प्राचार्य तथा स्थानीय सहायक केंद्राध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह पंवार, दगडू बिरला, सहायक केंद्राध्यक्ष जमरे द्वारा कक्षा 12 वीं के 144 परीक्षार्थियों का गुलाब का फूल देकर तिलक कर मिठाई खिलाकर स्वागत करते हुए प्रवेश देकर शांत चित्त होकर परीक्षा देने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

राष्ट्रीय विधिक शिविर में आगामी लोक अदालत की दी जानकारियां

माही की गूंज, थांदला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा के मार्गदर्शन में तथा किसना अतुलकर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ एवं तहसील विधिक सेवा समिति थांदला के अध्यक्ष जय पाटीदार, व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग-1 थांदला ने 03 मार्च को तहसील थांदला में हाट बाजार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अपर जिला न्यायाधीशध्सचिव किसना अतुलकर ने शिविर का उद्देश्य समझाते हुए बताया कि निःशुल्क विधिक सलाह एवं आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क विधिक सहायता भी हितग्राही व्यक्तियों को प्रदान की जा सकती है और विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित विभिन्न लोकोपयोगी एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। न्यायाधीश जय पाटीदार द्वारा आगामी माह में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत 11 अप्रैल 2020 के संबंध में जानकारी दी गई। शिविर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोकसिंह चौहान, पुलिस प्रशासन एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण, ग्रामीणजन एवं हितग्राहीगण उपस्थित थे।

शिक्षा के नाम पर चल रहा गोरखधंधा, आंख मूंद कर दे रहे स्कूलों को मान्यता

स्थान कहीं, संचालित कहीं ओर हो रही निजी स्कूल

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले भर में कथित तौर पर नीजि स्कूलों के नाम पर जो गड़बड़ झाला चल रहा है, उस पर न तो प्रशासन संज्ञान ले रहा है और ना ही संबंधित विभाग, जिनके द्वारा स्कूलों को मान्यता दी जाती है। उसके द्वारा बगैर सत्यापन किए ही स्कूलों को किस आधार पर मान्यता दी जा रही है, इसे लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। जिले के शिक्षा विभाग द्वारा 'रौनक एक्सीलेंस इग्लिंश मीडियम स्कूल ' को मान्यता दी गई है, उसका स्थान विभाग के पोर्टल पर करड़ावद छोटी बताया गया है, जबकि हमारी टीम द्वारा मौके पर जाकर इसकी पुष्टि करना चाही तो करड़ावद छोटी में न तो पूर्व में इस प्रकार की स्कूल संचालित हो रही थी और ना ही वर्तमान में इस नाम का स्कूल वहां संचालित हो रहा है। काफी पूछताछ करने बाद हमें बताया गया कि उक्त रौनक एक्सीलेंस इग्लिंश मीडियम स्कूल झाबुआ नगर में ही ज्योति भवन के पीछे एलआईसी कालोंनी में 5 फीट की गली जिसमें एक आटों भी नहीं जा पाता, ऐसे स्थान पर नाम मात्र के लिए प्रकाश मेड़ा के निवास पर किराए के भवन में संचालित हो रहा है।

इस गली कूंचे में सचांलित हो रही स्कूल में सिर्फ एक ही कमरे में बच्चों को ठूंस-ठूंस कर भरा जाता है। जबकि जिले के शिक्षा विभाग ने 31 मार्च 2022 तक जारी की गई मान्यता के पत्र में इस स्कूल को करड़ावद छोटी में इन्दौर-अहमदाबाद राज मार्ग पर होना बताया है। संबधित स्कूल संचालक को उनके आवेदन 25-2-2019 के अनुसार 1 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2022 तक की कालावधि के लिए जिले के शिक्षा विभाग ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन स्कूल की मान्यता का प्रमाणपत्र जारी किया है।

सबसे मजेदार तथ्य तो यह है कि जिस स्थान के लिए स्कूल की अनुमति शिक्षा विभाग द्वारा दी गई है। वह उस स्थान पर है ही नहीं। अर्थात करड़ावद छोटी की बजाय यह स्कूल एलआईसी कालोनी में चल रही है। वह भी पांच फिट की गली में केवल एक ही कमरे में। दी गई अनुमति पत्र के अनुसार स्कूल का क्षेत्रफल 16000 वर्ग फीट बताया है व स्कूल भवन का क्षेत्र फल 2600 वर्गफीट का दर्शाया है, वही खेल मैदान भी बताया गया है जो 12000 वर्गफीट का दर्शाया गया है। स्कूल में कुल 8 कक्ष बताए गए है तथा कार्यालय एवं भंडार के लिए अलग-अलग कक्षों का होना भी दर्शाया है। और तो और स्कूल में घंटी तक नहीं दिखाई दी है। बीआरसी द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में इस स्कूल के लिए जो अनुसंशा की है तथा शिक्षा विभाग झाबुआ ने अनुमति दी है, वह पूरी तरह स्कूल के मामले में कहीं भी लागू नहीं हो रही है। इससे तो लगता है कि नियमों को तांक पर रख कर तथा संबंधित स्कूल संचालक से गांधी छाप से अनुग्रहित होने के चलते इस प्रकार से फर्जी मान्यताएं दी जा रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को मानक स्तर की शिक्षा मिले इसके लिए स्कूलों में पूरी तरह से सभी खाना पूर्ति होना चाहिए। किन्तु चंद चांदी के टूकड़ों के लिए अपने जमीर को बेच कर इस तरह से स्कूलों को मान्यता देने का फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से चल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी जिनका दायित्व होता है कि वे ऐसे मान्यता दिए जाने वाली स्कूलों का निरीक्षण करके उनके द्वारा नियमों के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है या नही इसका स्वयं को भी सत्यापन करना चाहिए। किन्तु बीआरसी के प्रतिवेदन के आधार पर इस तरह गलत मान्यताएं देने के लिए क्या उनकी भी जिम्मेदारी नही होती है? इस पर भी ध्यान देना जरूरी है।

सबसे महत्वपूर्ण बात तो हमारे संज्ञान में यह भी आई कि एलआईसी कॉलोनी की जिस गली में यह स्कूल संचालित हो रही है उस गली के बाहर बच्चों के खड़े होने तक की जगह तक नहीं है। क्योंकि 5 फीट चौड़ी गली में एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा नहीं रह सकता है। इतनी संकरी गली के अंदर स्कूल का संचालन किया जाना कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जबकि मुख्यालय पर जिले के मुखिया कलेक्टर के होते हुए भी इस प्रकार का शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा करके धंधा चल रहा है तो जिले के अन्य स्थानों पर क्या हालात होंगे यह भी विचारणीय प्रश्न है। एलआईसी कालोनी में संचालित इस नीजि स्कूल में कक्षा एलकेजी से लेकर आठवीं तक एक ही कमरें में बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जा रही होगी इसका निरीक्षण भी आज तक न तो बीआरसी ने किया और ना ही जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से किसी जिम्मेदार ने। स्कूल के लिए जो निर्धारित मापदंड होना चाहिए उसमें से किसी की भी पूर्ति यहां दिखाई नहीं दी। मान्यता पत्र में जो शर्तें उल्लेखित की गई है वे केवल कागजी ही साबित हो रही है। बीआरसी ने इस स्कूल के लिऐ मान्यता देने के लिए निरीक्षण कर जो प्रतिवेदन दिया है वह पूरी तरह से मिथ्या ही साबित हो रहा है। बिना किसी वजूद के सभी सुविधाओं को अपने प्रतिवेदन में दर्शा कर मान्यता दिलाने का काम किया है। इसके पीछे बड़ी सौदे बाजी से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सरकार से अनुदान के साथ ही अन्य सुविधाएं लेने के नाम पर स्कूल संचालक ने बीआरसी एवं शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों से सेंटिंग कर के ही कथित तौर पर स्कूल के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए झुठी जानकारी देकर केवल औपचारिकता पूरी करने के नाम पर करड़ावद छोटी की बजाय झाबुआ में स्कूल चलाने का काम किया है। यदि इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाऐ, बीआरसी के प्रतिवेदनों को देखा जाए तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आंख मूंद कर मान्यता देने की बात को समझा जाऐ तो तय है कि स्कूलों को मान्यता देने के नाम पर क्या कुछ नहीं किया गया हुआ होगा। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर इसकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। यह तो सिर्फ एक मामला संज्ञान में आया है। जिले में इस तरह के न जाने कितने स्कूलों को इस प्रकार की मान्यताएं दी गई या दिलवाई गई होगी वह भी जांच का विषय है।

पोर्टल पर डाला गया स्कूल की मान्यता का प्रमाण पत्र।

रोनक एक्सीलेंन्स इग्लिश मीडियम स्कूल लग रही पांच फिट की गली के एक कमरे में।

इनका कहना है

आपके पास जो मान्यता का रिकार्ड उपलब्ध है। हमें वाट्सप पर डाल दो हम चेक कर लेते है। इस स्कूल को मान्यता झाबुआ के लिए ही दी गई है। किराड, बीआरसी झाबुआ।

निजी स्कूलों की मान्यता के आवेदनों के प्रस्ताव बीआरसी द्वारा दिया जाता है तथा उनके प्रस्ताव एवं अनुशंसा पर ही मान्यता के प्रमाण पत्र जारी होते है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं मौके स्थान पर नहीं जाते है। इसके लिए बीआरसी ही जिम्मेदार रहते है।

एम.एस. सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी, झाबुआ।

सड़क पर संदिग्ध अवस्था में मिले दो शव

माही की गूंज, बनी/रायपुरिया

रायपुरिया थाने के झकनावदा चौकी अंर्तगत ग्राम बोलसा के वाटर फिल्टर प्लांट के समीप मंगलवार सुबह सड़क पर एक महिला और पुरुष की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर रायपुरिया थाना पुलिस सहित आला अफसर मौके पर कुछ ही सयम पर पहुंचे। महिला और पुरुष के शरीर पर चोट के कई निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।मामले में पुलिस द्वारा अभी कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन आशंका जताई जा रही हैं कि मामला अवैध संबंधों को लेकर हत्या का हो सकता है। सड़क पर महिला और पुरुष के शव बीच करीब 50 फीट की दूरी मिले है। मौके पर एक मोबाइल, मोटरसाइकिल की चाबी, सेवपरमल और महिला के पास लाल कलर की चप्पल पड़ी है। लाशों की स्थिति देख कोई बड़ी घटना का होने का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मृतकों की पहचान कचराखदान की हुमली बाई पति वरसिंग भाभर और युवक बसंतीलाल पिता माड़िया वड़किया लामडीपाडा के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो सकेगा। थाना प्रभारी कैलाश चौहान के अनुसार घटना को एक्सीडेंट का रूप दिया है। मगर ऐसा लगता नहीं है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच हर एंगल से कर रही हैं। मौके पर फॉरसिंक अधिकारी ने भी जांच की है।

कोई वाहन नहीं मिला आसपास

दोनो मृतक महिला-पुरुष लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हैं और रात से दोनों घर से गायब थे। लेकिन दोनो में से किसी के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। घटना स्थल पर देख कर पता चलता है कि दोनों शव इस तरीके से फेंके गए है कि देखने पर दुर्घटना लगे। किसी चलते चार पहिया से फेंके जाने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। जिससे शरीर पर दुर्घटना में लगी चोट के निशान बनाए जा सके। घटना स्थल या उसके आसपास कोई वाहन जप्त नहीं हुआ। जिससे दुर्घटना के एंगल पर सवाल उठ रहे हैं। उक्त मार्ग अब पूरी तरह से चालू है और रात तक वाहन यहां से गुजरते रहते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भी हुआ वो देर रात और सुबह के बीच हुआ होगा। जब मार्ग पर आवाजाही न के बराबर होती हैं।

विधायक मेड़ा ने किया तालाब का भूमिपूजन

माही की गूंज, रायपुरिया/बनी। पेटलावद विधायक वालसिंग मेड़ा ने ग्राम कचराखदान में बनने वाले तालाब का भूमिपूजन किया। ग्राम कचराखदान में आरईएस विभाग 49.61 लाख रुपए की लागत से यह तालाब बनाएगा। कार्यक्रम में विधयाक वालसिंग मेड़ा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्रपालसिंह सलूनिया, जिला पंचायत सदस्य शारदा अमरसिंग डामोर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जीवन ठाकुर आईटी सेल अध्यक्ष विक्रम चावड़ा ने पूजा अर्चना कर भूमिपूजन किया। जिसके बाद आम सभा में विधायक मेड़ा सहित अन्य अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मेड़ा ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही सभा को जीवन ठाकुर ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सरपंच सविता गुलसिंग, सचिव राणा, पूर्व सरपंच लालू वसुनिया पंच एवं ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन नरेंद्रपाल सिंह सलूनिया ने किया। आभार ऋषभ गुप्ता ने माना।

सेमीफाइनल लाइन अप तय, कल खेले जाएंगे अंतिम चार के दोनों मुकाबले

भारत फाइनल के लिए इंग्लैंड से भिड़ेगा

टी-20 महिला विश्व कप 2020

04 मैच भारत ने ग्रुप में खेले और चारों में जीत हासिल की

04 मैच में से इंग्लैंड को तीन में जीत मिली, एक में हार झेलनी पड़ी

07 बार भारत ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, तीन बार सेमीफाइनल में हारा

सिडनी | एजेंसियां

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जारी आईसीसी टी-20 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए गुरुवार को अंतिम चार के पहले मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी। 2018 में हुए पिछले टूर्नामेंट में भी दोनों टीमें सेमीफाइनल में भिड़ी थीं जिसमें भारत हार गया था।

दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोनों मुकाबले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे। भारत ने ग्रुप-ए में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई जबकि इंग्लैंड की टीम ग्रुप-बी में दूसरे स्थान पर रही। ग्रुप-ए में ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे स्थान पर रही।

रद्द मैच से हुआ फैसला : सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का फैसला सोमवार को न्यूजीलैंड पर ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ हो गया था। पर ग्रुप-बी में कौन शीर्ष पर रहेगा, इसका फैसला दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के मुकाबले के बाद हुआ। दोनों टीमों का मैच एक भी गेंद फेंके जाने से पहले बारिश से रद्द हो गया। इस तरह दोनों को एक-एक अंक मिला। इससे दक्षिण अफ्रीकी टीम सात अंक के साथ ग्रुप-बी में शीर्ष पर पहुंच गई। इंग्लैंड के चार मैचों से छह अंक रहे।

भारत अजेय रहा : पहली बार फाइनल में जगह बनाने की कोशिशों में जुटी भारतीय टीम ने ग्रुप-ए में अपने सभी चार मैच जीत कुल आठ अंक के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया के तीन जीत से छह अंक जबकि दक्षिण अफ्रीका के तीन जीत और एक रद्द मैच से सात अंक हुए।

एक मैच के दौरान शॉट खेलती भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा।

ऑस्ट्रेलिया की पैरी चोट से बाहर

सिडनी। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। उसकी स्टार ऑलराउंडर एलिस पैरी पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण विश्व कप से बाहर हो गई। सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की करीबी जीत के दौरान रन आउट करने का प्रयास करने के बाद पैरी को लड़खड़ाते हुए बाहर जाते देखा गया था।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि पैरी अब टूर्नामेंट में नहीं खेल सकेंगी। चोट की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह इस महीने होने वाले ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भी उपलब्ध नहीं रहेंगी। टीम डॉक्टर पिप यंग ने बयान में कहा, एलिस के दाएं पैर की मांसपेशी में शीर्ष ग्रेड की चोट है जिसके कारण उन्हें खेल से लंबे समय तक दूर रहना पड़ सकता है।

पाक और थाईलैंड का मैच धुला

• नटकन चंतम, बल्लेबाज, थाईलैंड

सिडनी। थाईलैंड के नटकन चंतम ने मंगलवार को विश्व कप में पहला अर्धशतक जड़ा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप बी का यह मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। थाईलैंड ने सलामी बल्लेबाजों चंतम (56) और नताया बूथेथाम (44) की पारियों से तीन विकेट पर 150 रन बनाए। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में टीम का सर्वोच्च स्कोर रहा। लेकिन लगातार बारिश के कारण पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए नहीं उतर सकी। चंतम और बूथेथाम ने पहले विकेट के लिए 93 रन जोड़कर थाईलैंड को शानदार शुरुआत दिलाई। थाईलैंड ने 10 ओवर में बिना विकेट 70 रन बनाए। चंतम ने टूर्नामेंट में पहली बार थाईलैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। वह हालांकि अर्धशतक पूरा करने के बाद डायना बेग को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठीं।

शेफाली टीम में नई ऊर्जा लाईं: ली

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली का मानना है कि भारत पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाएगा। इसका कारण उन्होंने टीम में 16 साल की शेफाली वर्मा जैसी स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी को बताया। शेफाली के अलावा अनुभवी लेग स्पिनर पूनम यादव ने भी शानदार प्रदर्शन किया है।

ली का मानना है कि विरोधी टीम विशेष प्रयास करके ही भारत को पहली बार फाइनल में जगह बनाने से रोक सकती है। शेफाली की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, सेमीफाइनल में वह बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। शेफाली ने शानदार प्रदर्शन किया है। वह भारतीय बल्लेबाजी में नई उर्जा लेकर आई हैं।

> पहले हमने जो भारतीय टीमें देखी, उनकी तुलना में यह बिलकुल अलग टीम है। इनके पास शेफाली वर्मा और पूनम यादव जैसी मैच विजेता हैं जो गेंद और बल्ले से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अब हरमनप्रीत कौर के पास ऐसी भी खिलाड़ी हैं जो बड़े खिलाड़ियों का साथ देती हैं और उनके विफल रहने पर योगदान देती हैं।
> -ब्रेट ली, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

आगे की सोच

विराट ने युवा पेसरों को लाने के संकेत दिए

• जसप्रीत बुमराह। भारतीय गेंदबाज

क्राइस्टचर्च। कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि भारतीय तेज गेंदबाजों की बढ़ती उम्र के कारण हमारे थिंक टैंक ने भविष्य में तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी तैयार करने की जरूरत महसूस की है।

उम्र का असर : हालांकि जसप्रीत बुमराह के कई और वर्षों तक टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करने की उम्मीद है। लेकिन इस साल 32 वर्ष के होने वाले इशांत और 29 साल के मोहम्मद शमी अपने खेल के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। उमेश यादव भी इस साल 33 साल के हो जाएंगे।

आगामी योजना को छिपाए बिना कोहली ने कहा, वे खिलाड़ी अब युवा नहीं होने वाले, इसलिए हमें सतर्क और जागरूक रहना होगा। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो उनकी जगह ले सकें। कई बार छोटे स्तर पर बदलाव का सामना करना पड़ता है। नई प्रतिभाओं पर ध्यान देने का संकेत देते हुए भारतीय कप्तान ने कहा, नवदीप सैनी पहले से टीम का हिस्सा हैं। साथ ही हमें यह पहचान करने की भी जरूरत है कि अगले तीन-चार खिलाड़ी कौन होंगे जो स्तर बरकरार रख सकें।

प्रसाद सहित पांच चयनकर्ता पद की दौड़ में

मुंबई। बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) राष्ट्रीय चयनसमिति के दो पदों को भरने के लिए पांच उम्मीदवारों का साक्षात्कार करेगी। इनमें पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद भी शामिल हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदनलाल, आर पी सिंह और सुलक्षणा नाइक की समिति ने 44 आवेदनों की जांच करने के बाद इन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाने का फैसला किया। बीसीसीआई सूत्रों ने मंगलवार को बताया, उन्होंने वेंकटेश प्रसाद, पूर्व स्पिनर सुनील जोशी, क्रिकेटर से कमेंटेटर बने एल शिवरामाकृष्णन, पूर्व मध्यम गति के गेंदबाज हरविंदर सिंह और पूर्व स्पिनर राजेश चौहान को बुधवार को होने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजित अगरकर ने भी आवेदन किया था लेकिन उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है।

जोकोविक और बार्टी की बादशाहत बरकरार

नई दिल्ली। सर्बिया के नोवाक जोकोविक और ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ताजा टेनिस रैंकिंग में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष पर बरकरार हैं। डब्ल्यूटीए की रैंकिंग में बार्टी शीर्ष पर कायम हैं जबकि रोमानिया की सिमोना हालेप अंक के साथ दूसरे नंबर पर हैं। स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनसिच को फायदा हुआ, वह 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पछाड़ एक स्थान आगे आठवें नंबर पर पहुंच गई हैं। एटीपी रैंकिंग में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को पछाड़ सर्वश्रेष्ठ तीसरी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं।

उपयंत्री भूरिया ग्रामीणों को दबाकर लगा शिकायत निपटाने में

छोटी ऐरन से हो रहे पीचिंग कार्य को रोका

माही की गूंज, पेटलावद। ग्राम बेडदा में बन रहे 66 लाख के तालाब को लेकर सुर्खियों में बने हुए उपयंत्री और ठेकेदार के हौसले बुलंद है। तालाब की अनियमितता को लेकर शिकायत करने वाले ग्रामीणों को उपयंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि बार-बार यदि शिकायत की तो जो थोडा बहुत पानी तालाब में जमा हुआ हैं, वो खाली कर दूंगा। आने वाले कई सालों तक निर्माण अधूरा ही रहेगा।

उपयंत्री भूरिया अब ग्रामीणों से तालाब निर्माण सही होने और निर्माण से संतुष्ट होने का लिख कर देने का दबाव बना रहा है। मामला भोपाल तक पहुंचने के बाद भी भूरिया अपनी कारस्तानी से बाज नही आ रहा हैं और तालाब में होने वाली पीचिंग में छोटी-छोटी गिट्टी नुमा पत्थर से की जा रही थी। जिसकी जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने कार्य रोक कर बड़े पत्थर से पीचिंग करने का कहा। तब से कार्य बंद कर दिया गया है। ग्राम बेडदा के ग्रामीण सगन सिंह, कमलसिंह मेडा, धारू मेडा आदि ने बताया कि उपयंत्री द्वारा ग्रामीणों पर तालाब के सही निर्माण होने का लिखवाया जा रहा है जबकि तालाब में जमकर घटिया निर्माण किया गया। बता दे कि मामले को लेकर विधायक, एसडीएम और गांव के जनप्रतिनिधि शिकायत कर चुके है। प्रकाशित खबर के बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में जरूर लिया और एसडीओ व उपयंत्री को झाबुआ तलब किया। उपयंत्री इस उपसंभाग में 8 सालों से पदस्थ है। उपसंभाग यहां से चला गया और फिर से आ गया, लेकिन सेटिंग के बल पर यह आज भी यहां जमे बैठे है। एक आश्चर्यजनक खबर यह भी मिल रही है कि विकासखंड 77 में से 50 से अधिक पंचायतों का प्रभार इनके पास है। उपयंत्री दिलीप भूरिया ग्रामीण और जनप्रतिनिधि की शिकायतों को झूठी बता कर कार्य गुणवत्ता वाला होना बता रहा हैं, जबकि कार्य का घटिया निर्माण सामने जब ही आ गया था। जब ठेकेदार और उपयंत्री को भरी हुई पड़ल खोद कर फिर से भरना पड़ी थी।

मस्ती, उल्लास और उमंग का पर्व भगोरिया

जिले में 3 से 9 मार्च तक भरेंगे भगोरिया हाट

माही की गूंज, झाबुआ। संजय भटेवरा

मस्ती, उल्लास और उमंग के पर्व भगोरिया का जिले में आगाज हो चुका है। यह वह पर्व है जिसका सभी जिलेवासियों को वर्ष भर इंतजार रहता है। भगोरिया हाट को स्थानीय भाषा में गुलालिया हाट भी कहा जाता है अर्थात गुलाल से खेली जाने वाली होली का आगाज इन हाट बाजारों से होता है। यह सांस्कृतिक पर्व अपने आप में विविधता, पारंपरिकता और आधुनिकता के साथ मान्य रीति-रिवाजों को सतरंगी रंग में समेटे हुए हैं।

इस पर्व की यह विशेषता है कि, इसमें प्रत्येक आयु वर्ग का व्यक्ति, चाहे वह वृद्ध हो या जवान या फिर छोटा बच्चा, महिला हो या पुरुष, हर वर्ग का व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यों को भूलकर केवल मस्ती और आनंद में डूब जाता है और जब व्यक्ति अपने अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर आनंदित होता है, तो उस क्षण की कल्पना शब्दों से परे है।

भगोरिया पर्व की विशेषताएं

आधुनिक समय में तो संचार के बहुत से साधन है, लेकिन प्राचीन समय में जब संचार के साधन बहुत कम थे, ऐसे समय में साप्ताहिक हाट बाजार संचार के साधन के साथ ही मेल-मिलाप व दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और वर्ष भर में एक बार लगने वाले भगोरिया पर्व की तो बात ही निराली होती है।

भगोरिया हाट में आने की तैयारिया काफी पहले से की जाती है। युवा वर्ग में एक जैसा ड्रेस कोड तय किया जाता है। महिला तथा युवतियां भी सज-धज कर एक जैसी वेशभूषा में भगोरिया हाट में शामिल होती है। इस पर्व में गहनों का विशेष महत्व रहता है। पुरुष तथा महिलाए दोनों ही चांदी से बने विभिन्न आभूषणों से लेस होकर भगोरिया हाट में जाते हैं। पारंपरिक वाद्ययंत्र ढोल, मांदल, मंजीरा तथा बांसुरी की मनमोहक तान पर हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता है। एक जैसी वेशभूषा में गरबा पाली व सामूहिक नृत्य इस पर्व की शोभा में चार चांद लगाते हैं, हालांकि आधुनिकता के इस युग में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ आधुनिक डीजे ने भी अपना स्थान बना लिया है। साथ ही सामूहिक नृत्य के साथ ही पारंपरिक लोकगीत व हास्य बाणों से माहौल को खुशनुमा बनाया जाता है। इस वार्षिक हाट बाजारों में पूरे दिन भर सांस्कृतिक रंगों की रंग-बिरंगी छटा बिखरती रहती है और शाम को सभी लोग अपने घरों की ओर लौट जाते हैं।

पारंपरिकता से आधुनिकता तक

परंपरागत रूप से भगोरिया में ग्रामीण अपनी वेशभूषा में आभूषण सहित तैयार होकर हथियारों के साथ शामिल होते थे, लेकिन धीरे-धीरे पारंपरिक वेशभूषा की जगह जींस-टीशर्ट व घाघरा-ओढनी की जगह सलवार-सूट व साड़ियों में बदलने लगी है। वहीं हथियारों को पुलिस ने प्रतिबंधित कर दिया। पहले लोग पैदल या बैलगाड़ियों में चलते थे, लेकिन अब मोटरसाइकिल, जीप व अन्य वाहनों से शामिल होते हैं। वहीं ग्रामीणों का खान-पान भी अब बदलने लगा है। शीतल पेय के साथ ही आईस्क्रीम, कुल्फी, कचोरी, समोसे व मावे से बनी मिठाइयां भी अब भगोरिया हाट बाजारों में बिकने लगे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र अब धीरे-धीरे कम होने लगे हैं, उसकी जगह आधुनिक वाद्य यंत्र लेने लग गए हैं। प्राचीन भगोरिया से आधुनिक भगोरिया तक अगर कुछ नहीं बदला है तो वह है चांदी के आभूषणों के प्रति लोगों का आकर्षण। चांदी के विभिन्न प्रकार के पुरुषों और महिलाओं के आभूषणों के प्रति हर वर्ग के लोगों का लगाव आज भी कायम है।

कहां कब भगोरिया हाट शेष

5 मार्च गुरुवार- फुलमाल, सोंड़वा, जोबट, पारा, हरिनगर, सारंगी, समोई और चेनपुरा।

6 मार्च शुक्रवार- कट्ठीवाडा, वालपुर, उदयगढ़, भगोर, मांडली और कालीदेवी।

7 मार्च शनिवार- मेघनगर, राणापुर, नानपुर, उमराली, बामनिया, झकनावदा, बलेडी, वही शनिवार को खवासा में भी भगोरिया हाट लगता जरूर है, प्रशासनिक व्यवस्था भी माकुल रहती है, लेकिन प्रशासनिक रिकॉर्ड में आज तक दर्ज नहीं है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने इसके लिए कोई प्रयास किया।

8 मार्च रविवार- झाबुआ, छकतला, सोरवा, आमखूट, झिरण, ढोलियावाड़, रायपुरिया, काकनवानी, कनवाड़ा, कुलवट।

9 मार्च सोमवार- अलीराजपुर, च.शे.आजादनगर, पेटलावद, रम्भापुर, मोहनकोट, कुंदनपुर, रजला, बड़गुड़ा तथा मेंड़वा।

पुलिस प्रशासन की कसौटी का पैमाना भी

अविभाजित जिले में लगने वाले भगोरिया हाट का पुलिस प्रशासन के लिए भी खासा महत्व है। भगोरिया पर्व को पुलिस प्रशासन की करावट का पैमाना भी माना जाता है। अर्थात जिस किसी क्षेत्र में भगोरिया हाट शांतिपूर्वक निपट गया, वहां की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार जिले के प्रशासन को भगोरिया हाट बाजार में सफलता के आधार पर रेंटिंग मिलती है। यानी पूरे जिले में शांतिपूर्वक भगोरिया संपन्न होने पर बधाई पुलिस कप्तान यानी एसपी को मिलती है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी भगोरिया को लेकर विशेष सतर्क रहता है।

पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्रों का भविष्य अधर में

शुल्क जमा करवाने के बाद भी नहीं मिल रहा बीएसडब्लू के छात्रों को प्रवेश

माही की गूंज, पेटलावद।

बीएसडब्लू के छात्र-छात्राओं के महाविद्यायल के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को महात्मा गांधी ग्रामोघोग विश्वविघालय चित्रकूट से संचालित महाविद्यालय से प्रति रविवार कॉलेज और बाकी के दिनों में फील्ड में जाकर पढाई कर अपनी शिक्षा पूरी करनी होती हैं। उक्त सुविधा का लाभ पेटलावद के समस्त 77 पंचायत के सैकड़ों गरीब परिवार छात्र-छात्राए उक्त शिक्षा के माध्यम से ले रहे थे। जिसमें सरकार की योजना अंतंगत एसटी व एसी के लिए उक्त शिक्षा की कोई शुल्क शासन द्वारा नहीं वसूला जा रहा है। जबकि पिछडा वर्ग और सामन्य वर्ग के छात्रों के लिए सशुल्क प्रवेश निर्धारित किया गया था। यहां पेटलावद महाविद्यालय में पिछले सत्र में उक्त संस्था के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की परीक्षा के बाद नये व पुराने प्रवेश बंद कर दिए गए थे। जिससे कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। छात्रों की शिकायतों और मीडिया में मामला आने के बाद महाविद्यालय में बीएसडब्लू में पढाई कर रहे छात्रों की पढाई पूरी करने के लिए प्रवेश का कार्य पुनः शुरू किया गया, जबकि नये छात्रों के प्रवेश के लिए बंद करवा दिया गया।

उक्त कोर्स की बची पढाई पूरी करने के लिए एसटी और एसी के छात्रो को तो प्रवेश मिलना शुरू हो गए, लेकिन महाविद्यालय पेटलावद व सरकार की लापरवाही के कारण द्वितीय व तीतृय वर्ष के पिछडा वर्ग और सामन्य वर्ग के छात्रों को शुल्क जमा करने के बाद भी प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। उक्त मामले के महाविद्यालय के बीएसडब्लू के द्वितीय वर्ष के छात्र चरणसिंह मंगरोलिया और संजय धनधोरिया और तृतीय वर्ष के अनमोल पंवार ने बताया कि हम सभी कॉलेज पेटलावद में हमारी आगे की पढाई पूरी करने के लिए द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने के लिए महाविद्यालय में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 4500/- लेकर पहुंचे तो महाविद्यालय पेटलावद में बीएसडब्लू की नोडल अधिकारी प्राचार्य किरण दुबे ने हमको प्रवेश देने से मना कर दिया और कहा कि प्रवेश तिथि निकल चुकी है, जबकि एसटी व एसी के छात्रों का प्रवेश अब भी जारी है। छात्र चरणसिंह ने बताया कि हमको कॉलेज प्रशासन की ओर से किसी प्रकार से प्रवेश तिथि की जानकारी नहीं दी गई।

वहीं दूसरे वर्ग के छात्रों के प्रवेश अभी भी चल रहे है। मेरे द्वारा आपकी सरकार आपके द्वार के बोलासा कैम्प में 21 जनवरी 2020 को शिकायत भी कर रखी है। जिसका कोई निराकरण अब तक नहीं हो सका है। मामले में छात्रों द्वारा महात्मा गांधी विश्वविघालय चित्रकूट से भी बात की तो वहां से भी यही जवाब मिला की बिना शुल्क वालों का प्रवेश होगा। आप शुल्क वालों का कुछ भी नहीं होगा। इसके पीछे क्या कारण है। इसकी भी जानकारी छात्रों को नही दी गई। शिकायतों के बाद भी परेशान छात्रों की सुध नहीं ली जा रही जबकि पूर्व की सरकार में उक्त कोर्स का संचालन जनअभियान परिषद् के माध्यम से सुचारू रूप से किया जा रहा था। छात्रों का कहना है कि बीएसडब्लू का कोर्स पूरा करने के लिए बीए या बीकॉम में प्रवेश नहीं लिया। अब बीएसडब्लू में प्रवेश नहीं मिलने से दोनों ओर से रह गए और एक वर्ष बर्बाद होने कगार पर पहुंच गया है। छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से मांग की है कि उक्त मामले में हस्तक्षेप कर सभी वर्गो के छात्रों को प्रवेश दिलवाया जाए।

दिनदहाडे हुई दो लाख की लूट

माही की गूंज, पेटलावद। नए थाना प्रभारी संजय रावत के पेटलावद थाना पदस्थ होते ही चोरों ने उनको चुनौती पेश करते हुए दिन दहाडे दो लाख की लूट को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को दोपहर सबसे व्यस्तम थांदला-बदनावर रोड पर होटल ऋतुराज के पास में अज्ञात लुटेरों ने बंधक बैंक के कर्मचारी के दुपहिया वाहन को रोक कर लूट लिया। लूट के शिकार बंधक बैंक के कर्मचारी के अनुसार उसके पास बैंक की दो लाख रूपये की रकम थी जो कि ग्रामीण क्षेत्र से कलेक्शन कर के बैंक लोटते समय दुपहिया वाहन पर आए लुटेरों ने लूट कर फरार हो गई। बैंक की ओर से थाना पेटलावद में रिर्पोट दर्ज कराई है। पुलिस ने भी घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच कर घटना स्थल की जांच कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। लूट की घटना होने की जानकारी वहां आसपास किसी को नहीं लगी। मामले में थाना प्रभारी संजय रावत ने बताया कि मामला बैंक से जुडा है और बैंक की और से रिर्पोट प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। इससे पहले भी डेली कलेक्शन वाली बैंक के कर्मचारी इस प्रकार खवासा, रायपुरिया, पेटलावद, हमीरगढ क्षेत्र में लूट का शिकार हो चुके है। पुलिस का कहना है कि अपराध ट्रेस करने के पूरे प्रयास किए जा रहे है।

खबर का असर माही की गूंज की खबर के बाद जागे सासंद

8 लेन एक्सप्रेस वे के पीड़ितों को लेकर मिले कलेक्टर से

माही की गूंज, झाबुआ।

थांदला में पिछले एक पखवाड़े से एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठे भारत माला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली-मुंबई के बीच बनने वाले 8 लेन एक्सप्रेस वे के मुआवजा पीड़ितों की आवाज बनने का काम माही की गूंज ने किया था। हमने पिछले अंक में 'सासंद जी! जरा इन पर तरस खाइए' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जो उस दिन झाबुआ जिले में हर किसी की जुबां पर था। इस लेख में उन मुआवजा पीड़ितों के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की वजह और जनप्रतिनिधियों द्वारा उनकी सुध न लिए जाने पर तीखे व्यंग्य कसे गए थे। जिसको पीड़ितों के साथ ही आमजन ने सराहा था। इस पर सुध लेकर पिछले गुरूवार को शाम को ही सासंद गुमानसिंह डामोर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर प्रबल सिपाहा से बात की। जिसमें उनको मुआवजा दिए जाने के साथ ही किसी वैकल्पिक स्थान दिए जाने की बात हुई। इस बैठक में सांसद डामोर के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष विश्वास सोनी, जनजातीय विकास मंच के कैलाश अमलियार, संजय भाभर आदि मौजूद रहे। हालांकि धरने पर बैठे लोग अभी भी वहीं डटे हुए है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन लिखित में कोई आश्वासन नहीं देता है, तब तक वह प्राण त्यागने तक बैठे रहेंगे। अब देखना होगा कि सासंद की यह मुलाकात कोई रंग लाती है या इन सबको लेकर सासंद वर्तमान में चल रहे संसदीय सत्र में इनके समर्थन में बात उठाने की हिम्मत दिखा पाते हैं या नहीं।

मार्च 2020 में आगामी 3 माह का राशन साथ मिलेगा

माही की गूंज, झाबुआ।

खाद्य विभाग के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वह राशन दुकान पर पहुंचने से पहले तीन माह के खाद्यान्न की राशि एवं पर्याप्त साधन ले जाए। 1 मार्च से ही दुकानों पर राशन वितरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। खाद्य विभाग ने सभी जनप्रतिनिधि ,ग्रामीण कर्मचारी, उपभोक्ता एवं समाजसेवियों से अनुरोध है कि यह सूचना अपने ग्राम पंचायतों के व्हाट्सएप ग्रुप में, सचिव के ग्रुप में, सरपंचों के ग्रुप में जनप्रतिनिधियों के ग्रुप में प्रेषित करें। आम उपभोक्ता को इस सूचना से अवगत कराने का प्रयास करने की अपील की है। विभाग के अनुसार अगर किसी ठेके पर विक्रेता द्वारा 3 माह का राशन देने से मना किया जाता है तो इसकी सूचना लिखित खाद्यान्न विभाग कलेक्टर कार्यालय झाबुआ को दें ताकि उचित कार्यवाही की जाएगी।

घोड़ों की खरीद-फरोख्त का मौसम

राकेश अचल
वरिष्ठ स्तंभकार

देश में मौसम लगातार करवट ले रहा है, लेकिन हमारे मध्यप्रदेश में इन दिनों घोड़ों को खरीद-फरोख्त का मौसम चल रहा है। मजे की बात ये है कि ये घोड़े सियासत के हैं और जनता इन्हें चुनकर सदन तक भेजती है। सुना जा रहा है कि इन दिनों घोड़ों की मंडी में कीमत 35 करोड़ तक जा पहुंची है।

पुराने जमाने से घोड़े सियासत की मजबूरी हैं, जब सत्ता के विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ किए जाते हैं तो सबसे पहले एक मजबूत कद-काठी के घोड़े की जरूरत पड़ती है। आगे-आगे ध्वजाधारी घोड़ा चलता है और पीछे-पीछे सेना। जो कोई घोड़े को रोक लेता है उसे सेना से मुकाबला करना पड़ता है, जो जीतता है घोड़ा उसका हो जाता है और राज्य भी। अब जमाना बदल गया है और अश्वमेघ का तरीका भी, लेकिन घोड़े नहीं बदले। वे पहले की ही तरह आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी सियासत को उनकी उतनी ही जरूरत है, जितनी कि पहले हुआ करती थी।

राजनीतिक दलों का घोड़ा प्रेम नया नहीं है।। हर दल में घोड़ों की इज्जत की जाती है। बिकाऊ घोड़े हर सत्ता के लिए जरूरी होते हैं, ये घोड़े ही सत्ता बनवाते भी हैं और गिराते भी हैं। एक जमाने में स्व. पीवी नरसिंहराव ने भी एक घोड़ा खरीदकर अपनी कुर्सी बचाई थी। भाजपा तो 2014 के बाद देशव्यापी अश्वमेघ विजयी अभियान पर निकली। उसने जहां-तहां इन्हीं बिकाऊ घोड़ों के बल पर अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया। अपवाद स्वरूप खुद भी परास्त हुई। घोड़े खरीदने और बेचने का अनुभव सबको नहीं होता। हर दल में इस व्यापार में सिद्धहस्त कुछ ही लोग होते हैं। मध्यप्रदेश में एक समय दिग्गी राजा ने बसपा के तमाम बिकाऊ घोड़े खरीद लिए थे।

मै भटककर अपने सूबे के बाहर निकल गया। बात मध्यप्रदेश की है। साल भर पहले घोड़े खरीदने में नाकाम रही भाजपा को अपनी पंद्रह साल पुरानी सत्ता से हाथ धोना पड़े थे। मंडी में घोड़े कम थे और ग्राहक ज्यादा इसलिए बात बनी नहीं ,लेकिन अब जब प्रदेश में राज्य सभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, एक बार फिर घोड़ों की खरीद-फरोख्त के चर्चे तेज हो गए हैं। पुराने यानि खग्गी घोड़ा कारोबारी रहे दिग्गी राजा का आरोप है कि भाजपा प्रदेश में घोड़ा व्यवसाय को प्रोत्साहित कर रही है। उनका आरोप है कि भाजपा ने उनके पाले के आधा दर्जन घोड़ों का अपहरण कर उन्हें एक होटल में बंधक बना लिया है।

दिग्गी राजा के आरोपों पर हम कभी अविश्वास नहीं करते क्योंकि वे पूरे आत्मविशास के साथ आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि भाजपा एक-एक घोड़े की कीमत 35 करोड़ तक लगा रही है। भाजपा ने कीमत किश्तों में देने का प्रस्ताव किया है ।जिन घोड़ों की कीमत लगाई गई उनमें से कुछ रस्सी तुड़ाकर कांग्रेस के अस्तबल में वापस लौट आए, उन्होंने बाकायदा हिनहिनाकर कहा कि भाजपा ने उन्हें खरीदने की कोशिश की। मजे की बात ये है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने अस्तबल में रह रहे घोड़ों से कहा है कि-श् यदि मुफ्त का माल मिल रहा है तो ले लो,कोई हर्ज नहीं ,बस अस्तबल मत बदलना।श

राज्य की सत्ता को साल भर से अस्थिर करने में नाकाम रहे भाजपा के अनेक घोड़ा व्यापारी दिल्ली में डेरा डेल हुए हैं। उन्होंने बाकायदा दिल्ली के आसपास अस्थाई अस्तबल भी बना लिए हैं। कहते हैं कि दिग्गी राजा की तरह भाजपा के पास घोड़ा व्यवसाय के महारथी कैलाश विजयवर्गीय,डॉ. नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग हैं। इन्हें बिकाऊ घोड़ों की नस्ल और कीमतें आंकने का अच्छा-खासा तजुर्बा है। विधानसभा चुनाव के बाद हालांकि इनका तजुर्बा ज्यादा काम नहीं आया,लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, भाजपा वैसे भी कभी हिम्मत न हारने वाली पार्टी है। भाजपा कितने भी राज्यों में चुनाव हारी हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दिल्ली चुनाव हारने के बाद भी भाजपा बंगाल जीतने के लिए अपने घोड़े खोल चुकी है।

आपको बता दें कि हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब श्घोड़ों की बिक्रीश् से है. असल में इस शब्द की शुरुआत कैंम्ब्रिज डिक्शनरी से हुई थी। करीब 18वीं शताब्दी में इस शब्द का इस्तेमाल घोड़ों की बिक्री के दौरान व्यापारी करने लगे, लेकिन इसके साथ किस्से जुड़े कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। यूं तो राजनीति में इस शब्द का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में इसका इस्तेमाल बढ़ा है। जब राजनीति में नेता दल बदलते हैं, या फिर किसी चालाकी के कारण कुछ ऐसा खेल रचा जाता है कि दूसरी पार्टी के नेता आपका समर्थन कर दें तब राजनीति में इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है।

सनद रहे कि हाल ही के दिनों में जिस प्रकार गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और कर्नाटक में राजनीतिक उथल-पुथल मची तो हॉर्स ट्रेडिंग के ही आरोप लगे। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों की खरीद-फरोख्त कर रही है, इसके अलावा कई विधायकों को डराया धमकाया भी जा रहा है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को लेकर भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे।

कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे पर लंबी चर्चा चली। अनौपचारिक चर्चा के दौरान मंत्रियों ने विधायकों की खरीद-फरोख्त के सामने आ रहे बयानों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का ध्यान आकर्षित किया। मंत्रियों ने कहा कि ऐसे बयान आ रहे हैं, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अपने विधायकों के संपर्क में रहो और विरोधियों को कड़ा जवाब देने के लिए भी तैयार रहो। मंत्रियों ने राज्यसभा चुनाव और विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले सामने आ रहे इन बयानों को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री नाथ ने मंत्रियों को अलर्ट रहने के साथ भाजपा के आरोपों का कड़ाई से जवाब देने को कहा है।अब देखिये आने वाले दिनों में क्या होता है ?

जशोदा बेन का किया गया स्वागत

माही की गूंज, झाबुआ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी का कालीदेवी मे जोरदार स्वागत हुआ। जशोदाबेन महाकाल दर्शन करके अहमदाबाद जाते समय ग्राम रामा में पवन भाई राठौड़ के घर पर छापरी के सरपंच दिनेश अमलियार ने आदिवासी प्रतीक चिन्ह आदिवासी गुड़िया तथा तीर-कमान, गोफन भेंट किया एवं फलाहार करवाया। इस अवसर पर उत्तम जैन, प्रकाश भूरा विनोद परमार तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422